नई दिल्ली
बुधवार
04 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 61
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त, जायसवाल....पेज-06

DELHIN/2014/58158

बिहार के जमुई, गयाजी और मुंगेर की परियोजनाओं...पेज-05

एक नजर

केंद्र सरकार ने नए विमान नियम किए अधिसूचित, जनवरी, 2027 से होंगे लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 90 साल पुराने विमान कानून की जगह 'भारतीय वायुयान नियम-2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से पूरे देश में लागू होंगे, जो पुराने विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे। हालांकि, मौजूदा नियमों की तुलना में नए नियमों में किए गए विशिष्ट बदलावों का तत्काल पता नहीं चल सका है। अधिसूचना के मुताबिक नए नियमों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुक करते समय किराये और सभी शुल्कों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा। ये जानकारी बुकिंग वेबसाइट और जारी टिकट, दोनों पर देनी होगी। ब्योरे में कुल रकम के साथ किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें भी अलग-अलग बतानी होंगी। किसी अन्य शुल्क की जानकारी भी देनी होगी। एयरलाइन कंपनियों के तय किए गए किराये की निगरानी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) करेगा। यह नियम भारतीय वायुयान विधेयक-2024 के तहत बनाए गए हैं, जिसने 90 साल पुराने विमान अधिनियम-1934 का स्थान लिया है। भारतीय वायुयान नियम-2026 के तहत किसी 'असाधारण स्थिति' में नागर विमानन मंत्रालय हवाई किराये के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों को 'असाधारण स्थिति' माना जाएगा। नियमों में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की राय में कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह जनहित में आवश्यक और उचित समझे जाने वाले निर्देश लिखित आदेश के जरिये जारी कर सकती है।

ईडी का श्रीनगर में आतंकी फंडिंग मामले में चार ठिकानों पर छापा

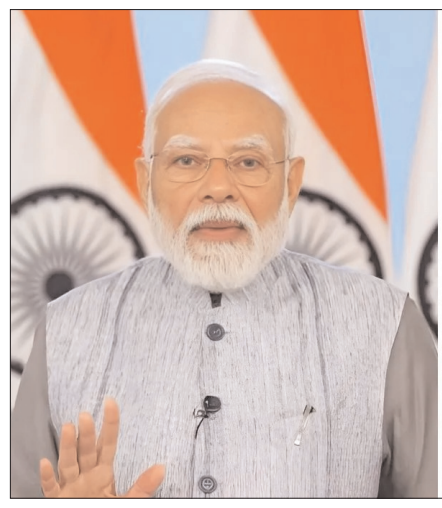


नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में मंगलवार को श्रीनगर के चार ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी उमर आदिल डार और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी के अनुसार, उमर आदिल डार प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय था। ईडी ने बताया कि आरोप है कि उमर आदिल डार को पहले उसके सहयोगियों के साथ बड़ी मात्रा में नकदी और प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आपत्तिजनक साहित्य के साथ पकड़ा गया था। जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में वह पहले करीब चार साल जेल में भी रह चुका है। ईडी का तलाशी अभियान अपराध से अर्जित धन का पता लगाने, वित्तीय नेटवर्क और फंडिंग के माध्यमों की पहचान करने तथा सीमा पार बैठे हैंडलरों से उनके कथित संबंधों की जांच के लिए चलाया जा रहा है। एजेंसी का उद्देश्य कथित आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाना भी है। मामले में आगे की जांच जारी है।

नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

पुणे देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं का केंद्र है: प्रधानमंत्री

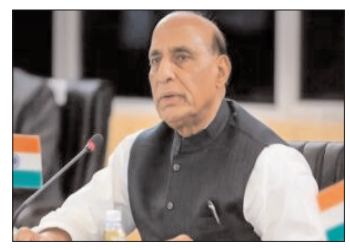
पुणे,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पुणे मेट्रो की लगभग 21,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और जनकल्याण के प्रति अपनी सरकार के समर्पण को दोहराया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 'शक्ति से सशक्तीकरण और सुशासन' के अपने नारे को दोहराते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि और गरीबी एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हाल के वर्षों में देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि के चलते सरकार को गरीबी दूर करने के प्रयास में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने मौसम की मार से प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने शहरों को देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केन्द्र बताते हुए कहा कि हमारे शहर केवल आवासीय स्थान नहीं हैं, बल्कि वे देश की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भी हैं। हमें देशभर के सैकड़ों छोटे शहरों को सक्रिय विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना होगा। मोदी ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और गरीबी कम करने के काम में देश की रफ्तार दुनिया में सबसे बढ़ कर है। श्री मोदी ने कहा, 'आज भारत वो देश है, जो सबसे तेजी से वृद्धि कर रहा है और गरीबी भी सबसे तेज गति से कम कर रहा है।' उन्होंने कहा कि ये दोनों 'सिद्धियां' एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है जिससे सरकार का बजट बढ़ा है, देशवासियों के कल्याण और विकास पर ज्यादा निवेश हो रहा है।





उन्होंने कहा, 'पहले जो पैसा, घोटालों और भाई भतीजावाद के लीकेज में जाता था, अब सीधा लाभार्थी तक पहुंच रहा है। जब देश के खजाने का पैसा, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो में लगता है, जब सरकार, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन पर निवेश बढ़ाती है, तब लोगों का जीवन भी सुधरता है और उनके लिए रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के घर, टॉयलेट, हर घर जल, गैस कनेक्शन, ऐसी सुविधाओं से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनका समय बच रहा है जिसका वे अपने परिवार के लिए दूसरे कामों पर उपयोग कर पा रहे हैं। श्री मोदी ने दस वर्ष पहले पुणे मेट्रो के पहले चरण की आधारशिला रखने के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि हिंजवड़ी से शिवाजीनगर तक के कॉरिडोर का उद्घाटन शहर के प्रमुख आईटी हब को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वहीं, आज शुरू की गई नई मेट्रो लाइन शहर के पुराने और नए हिस्सों को आपस में जोड़ेगी। पुणे को विचारों का एक ऐतिहासिक केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहर ने लगातार देश और समाज को दिशा देने का काम किया है। आज पुणे आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, स्टार्टअप, नवाचार और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में विकसित भारत की नई ऊर्जा को आगे बढ़ा रहा है। यह युवाओं की आकांक्षाओं का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा, 'ऐसी स्थिति में यहां मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार पुणे शहर के विकास को नई गति प्रदान करेगा। हमारी सरकार का हमेशा से मंत्र रहा है कि गरीब को सशक्त करो तो गरीब में अपनी गरीबी से बाहर निकलने का साहस आ जाता है। मुझे याद है, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो इसी सोच के साथ मैंने गरीब कल्याण मेले की परंपरा शुरू की थी। इन मेलों में गरीब कल्याण की स्कीमों की डिलिवरी पर फोकस होता था। गरीबों को मंच पर आमंत्रित किया जाता था। वे गरीबी को परास्त करने का संकल्प लेते थे, एक आत्मविश्वास लेकर आयोजन से लौटते थे।' उन्होंने कहा , 'वह जो काम 25 साल पहले मैंने शुरू किया, वह आज तक अनवरत चल रहा है। इसी को मैं, पावर टू एम्पावर (शासन की शक्ति से जनता जनार्दन का सशक्तीकरण) कहता हूँ।

युद्ध की बदलती चुनौतियों के लिए सेना को नई प्रौद्योगिकी और ताकत से लैस करने की तैयारी: राजनाथ



नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आधुनिकीकरण बजट को साल दर साल बढ़ाया और खर्च भी किया है। आज के बदलाव के समय में तकनीक युद्ध का अभिन्न अंग है। नए हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। सेनाएं भी अच्छी तरह समझती हैं कि सरकार उनकी जरूरतों के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए वे अति महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता पर रखकर बजट का अच्छे से इस्तेमाल भी करती हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल आधुनिक उपकरण हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें हमारी सेनाओं की जरूरतों के अनुरूप तकनीक का विकास हो, भारतीय उद्योग की भागीदारी बढ़े और देश की रणनीतिक निर्भरता कम हो। आधुनिकीकरण का मतलब केवल नए हथियार और उपकरण खरीदना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सेना की ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करना, उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करना और देश के भीतर ऐसी क्षमताओं का विकास करना, जिन पर हम लंबे समय तक भरोसा कर सकें। इसी दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सामरिक स्वायत्तता और स्वदेशी तकनीकी क्षमता हमारी देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में सफलता की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मानव संसाधन है। जिस तेजी से दुनिया में युद्ध और युद्ध-लड़ने वाले सिस्टम में बदलाव आ रहा है, वह हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है कि हमारी सेनाएं और उनकी फॉर्मेशन भी आधुनिक युद्ध की पहुंच आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने अपने स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में लगातार सुधार और बदलाव किए हैं।

उदाहरण के लिए हमारी सेना में बनाई गईं असनी, भैरव और शक्तिबाण प्लाटून जैसी नई फॉर्मेशन आज की ऑपरेशनल जरूरतों और युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियारों और मिसाइलों के निर्माण में हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। लघु उद्योगों से लेकर बड़ी कंपनियां तक आज रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी प्रगति रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में भी दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2014-15 में हमारा रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये हो गया। हमारा रक्षा निर्यात वर्ष 2014 में दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था, जो अब बढ़कर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कॉप-31 में जलवायु वित्त, शमन और अनुकूलन के परिणाम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत की प्राथमिकताएं: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉप- 31 में समाधान आधारित और समानता के सिद्धांत पर केंद्रित जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएं पूर्वानुमानित जलवायु वित्त, शमन एवं अनुकूलन संबंधी परिणाम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और न्यायसंगत बदलाव होंगी। भारत का प्रयास होगा कि सम्मेलन में केवल प्रतिबद्धताओं तक सीमित न रहकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए। मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सीओपी 31 में वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा। क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करना और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधान भारत के दृष्टिकोण के प्रमुख आधार होंगे। इस दिशा में भारत जी-77 एवं चीन, एलएमडीसी और अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु सम्मेलन के उद्देश्यों और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक प्रयासों में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु वित्त भारत की प्रमुख प्राथमिकता होगी। भारत सम्मेलन में जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्णय लेने की मांग करेगा।

मंत्री ने कहा कि विकसित देशों पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। यह वित्त पूर्वानुमानित, मुख्य रूप से सार्वजनिक और रियायती होना चाहिए तथा विकासशील देशों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु शमन और वैश्विक समीक्षा प्रक्रिया देशों के नेतृत्व में, सहयोगात्मक और गैर-दंडात्मक होनी चाहिए।

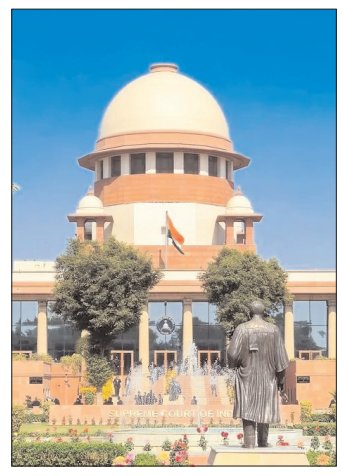
दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के बाजारों में प्रतिबंधों के बावजूद अलग-अलग तरह के पटाखे बेचे जाने से जुड़ी एक अखबार की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया और केंद्र से कहा कि वह उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करे। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को एक अंग्रेजी अखबार की खबर में छपी तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि कल के आदेश के बावजूद अब दुकानों में सबकुछ उपलब्ध है। कृपया इस पर ध्यान दें। 2 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगा प्रतिबंधीदिवाली पर दो दिनों के लिए सशर्त हटाने आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के दौरान जलाए जा सकेंगे। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है।

वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी तक टली

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 31 दिसंबर तक लिखित दलीलें जमा करें पक्षकार

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 21 जनवरी तक के लिए टाल दी है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को आदेश दिया कि वे 31 दिसंबर तक अपनी लिखित दलीलें और दस्तावेज जमा कर कानूनी प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कर लें। सुनवाई के दौरान नोडल काउंसिल ने जानकारी दी कि पहले इस मामले में 5 मुख्य याचिकाओं को आधार माना गया था, जबकि अन्य 135 याचिकाओं को अंतरिम आवेदनों में बदल दिया गया था। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि ये 5 मुख्य याचिकाएं चुनौती के सभी कानूनी आधारों को पूरी तरह से कवर नहीं करती हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आवेदन देने वाले आवेदकों को



दो हफ्तों के भीतर स्वतंत्र रूप से नई रिट याचिकाएं दायर करने की इजाजत दे दी ताकि उनके सभी कानूनी तर्कों को विस्तार से सुना जा सके।

गौरतलब है कि संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी से यह कानून अस्तित्व में आया था। इसके खिलाफ देशभर से 100 से अधिक याचिकाएं दायर कर इसे असंवैधानिक और वक्फ संपत्तियों के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया गया। सितंबर 2025 में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन प्रथम दृष्टया कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। इनमें वक्फ बनाने के लिए इस्लाम का पालन करने की पांच साल की शर्त (नियम बनने तक), धारा 3ष्ट के तहत नामित अधिकारी को दी गई विशेष शक्तियां और केंद्रीय वक्फ परिषद तथा राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित करना शामिल था। कोर्ट ने नोडल काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी फैसलों और दलीलों का एक संकलन तैयार करें, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करेंगे।

देश की बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तेज मंजूरी प्रक्रिया और आसान फंडिंग जरूरी: पीयूष गोयल

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश की जैव अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी) को गति देने के लिए नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने, स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण को आसान बनाने और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि गोयल ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में 'भारत में बायोइकोनॉमी अवसर: नवाचार और विकास को बढ़ावा देने में स्टार्टअप्स की भूमिका' विषयक एक उच्च-स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही। इसका आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग



(डीपीआईआईटी) ने नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब के सहयोग से किया था। गोयल ने अपने संबोधन में भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं और उद्यमशीलता प्रतिभा का उपयोग करके भारत को बायोइकोनॉमी में विश्व स्तर पर अग्रणी देश (ग्लोबल लीडर) के रूप में स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने तेजी से मंजूरी मिलने, वित्त तक बेहतर पहुंच, साझा बुनियादी ढांचे और उद्योग, शिक्षा जगत तथा सरकार के बीच मजबूत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने गोलमेज बैठक से निकले सुझावों पर निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का आह्वान किया। इस बैठक में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों और बायोफार्मा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य भारत की बायोइकोनॉमी के विकास को तेज करने के उपायों पर चर्चा करना था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 'एक्स' पर जारी पोस्ट में लिखा कि भारत के बायोफार्मा और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य चुनौतियों पर बात हुई और विकास के नए अवसरों को खोलने पर विचार किया गया।

नई पीढ़ी अपनी जड़ों, भाषा और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़े: सीतारमण

वाराणसी,एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, भाषा और शास्त्रीय परंपराओं की ओर लौटना चाहिए। भारत की विविधता और एकता को बनाए रखने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों से भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों को समझने तथा देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजने का आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री मंगलवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के स्वतंत्रता भवन सभागार में कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने महान संगीतकार के सम्मान में 250 रुपये के स्मारक सिक्के का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी बीएचयू के भारतीय ज्ञान परंपरा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-आईकेएस) की ओर से किया गया। वित्त



मंत्री ने बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के साथ दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। निर्मला सीतारमण ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर की संगीत रचनाओं की विशिष्टता, आध्यात्मिकता और विद्वत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी कृतियां केवल संगीत रचनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत का विस्तृत परिचय भी कराती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थस्थलों और मंदिरों की विशेषताओं को स्वर दिया।

काशी का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दीक्षितर ने देवी की स्तुति में काशी विश्वलक्ष्मी का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में मंदिरों के पवित्र वृक्षों (स्थलवृक्ष), आसपास की नदियों, पर्वतों और भौगोलिक विशेषताओं का भी उल्लेख मिलता है। इस लिहाज से उनकी कृतियां किसी स्थान की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विशेषताओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वित्त मंत्री ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं की तुलना प्रसिद्ध यात्रा-पुस्तक श्रृंखला 'लोनली प्लैनेट' से की। उन्होंने कहा कि आज किसी अनजान स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लोग गूगल का सहारा लेते हैं, जबकि पहले यात्री 'लोनली प्लैनेट' जैसी पुस्तकों के माध्यम से किसी स्थान के दर्शनीय स्थलों, खानपान और विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते थे। उन्होंने कहा कि दीक्षितर की रचनाएं भी इसी तरह भारत के विभिन्न स्थानों, मंदिरों और उनकी विशिष्टताओं से परिचित कराती हैं। महान चित्रकारों की तरह वे अपनी प्रत्येक रचना में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ते थे। वे अपनी कृतियों में 'गुरुगुह' नाम की मुद्रा का प्रयोग करते थे और राग का नाम भी रचना में समाहित करते थे।

दिल्ली में 7000 किलो मिलावटी खोया जब्त, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7,000 किलो मिलावटी और दुर्गंधयुक्त खोया जब्त कर उसे उसे नष्ट किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से कार्रवाई के प्रत्येक पहलू की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि संदिग्ध खाद्य सामग्री किसी भी स्थिति में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होकर लोगों तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। त्योहारों के समय लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मिलावटखोरी करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य खराब और संदिग्ध खाद्य सामग्री को बाजार के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने से रोकना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मोरी गेट की खोया मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग का यह चौथा ऑपरेशन है। विभाग की टीम ने मोरी गेट की खोया मंडी में अभियान के दौरान 44 निगरानी नमूने एकत्र किए। इनकी मौके पर ही 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' मोबाइल टेस्टिंग सुविधा के माध्यम से प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें 35 नमूने जांच में फेल पाए गए। इसके अलावा दो अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में संदिग्ध सामग्री में दूध पाउडर, वनस्पति और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों से संबंधित जानकारी सामने आई है। इन सामग्रियों के संबंध में आगे की जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सतर्कता, मेहनत और समय पर की गई कार्रवाई से मिलावट जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

उन्होंने टीम को आगे भी इसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की खुशियों में मिलावट करने वालों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है। सरकार का उद्देश्य केवल मिलावटी खाद्य पदार्थों को पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना भी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया है। विभाग की ओर से अब तक की गई कार्रवाई के तहत 4 सितंबर को 2,830 किलो खोया, 8 सितंबर को 610 किलो खोया और 23 अक्टूबर को 520 किलो खोया नष्ट किया गया। इसके बाद 3 नवंबर को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में कार्रवाई करते हुए लगभग 7,000 किलो अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया नष्ट किया गया। इस तरह विभाग अब तक कुल 10,660 किलो खोया नष्ट करा चुका है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के मामले में स्वत: संज्ञान से किया इनकार



शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। आज कुछ वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के आचरण पर स्वत: संज्ञान लेने की मांग की। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने वकीलों से कहा कि वे सभी उपलब्ध दस्तावेज के साथ एक उचित याचिका दायर करें, जिस पर अदालत विचार करेगी। मेंशनिंग के दौरान वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ 'एके-47 का इस्तेमाल' और 'काले कोट के गुंडे' जैसी टिप्पणियां की गईं। एक वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप हमारे मुखिया हैं। अगर आप इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हैं, तो हमें तसल्ली मिलेगी। तब कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दायर करें, कोर्ट उस पर विचार करेगी। दरअसल, 2 नवंबर को ये पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र होकर शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई झड़प के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनके पुराने पदों पर वापस तैनात करने की मांग कर रहे थे।

यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब एक बहस के दौरान वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद वकीलों ने पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठाए थे। वकीलों ने आरोप लगाया कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने अपनी रिवॉल्वर दिखाकर उन्हें डराया-धमकाया। वशिष्ठ को वकीलों को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने संत परमानंद अस्पताल में आईवीएफ सेंटर का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित संत परमानंद अस्पताल में नवनिर्मित आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञ सेवाओं से युक्त यह केंद्र अनेक परिवारों के जीवन में नई आशा और खुशियां लाने का माध्यम बनेगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता स्वागत योग्य है। इस नई पहल के लिए संत परमानंद अस्पताल के चिकित्सकों एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि संत परमानंद अस्पताल दिल्ली के मध्य में स्थित 153 बिस्तरों वाला एक बहु-विशेषज्ञ अस्पताल है। महज 13 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टरों की टीम के दम पर, इस अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। अस्पताल किसी भी प्रकार की सर्जरी या बीमारी के लिए सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है और अस्पताल के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में जोड़ों के प्रतिस्थापन की सर्जरी, आघात, गहन चिकित्सा, नेत्र देखभाल, उच्च जोखिम वाली प्रसूति और प्रसव केंद्र शामिल हैं। संत परमानंद अस्पताल एक समाज-आधारित संस्था है जो मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। वंचितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है।

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिसकर्मियों से किया संवाद, साहस और समर्पण को सराहा

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को 'उत्सव सदन' किंग्सवे कैंप में पुलिसकर्मियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार समेत पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित रखने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता को सराहा।

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को बेहतर कार्य-परिस्थितियों, कल्याणकारी उपायों और आधुनिक संसाधनों के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उनसे आग्रह किया कि वे पारंपरिक और नए तरीकों के जरिए नागरिकों के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का काम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य लोगों का भरोसा जीतना, उन तक पहुंच सुनिश्चित करना और हर नागरिक की सेवा सहानुभूति, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ करना होना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा हमारा विजन एक ऐसी दिल्ली का है, जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।



ओखला में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और चश्मा चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार



सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर की गई चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी और चोरी का सामान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप, एक अन्य लैपटॉप, धूप के चश्मे तथा वारदात में इस्तेमाल की गई यामाहा एफजेड मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने में पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि ओखला फेज-1 स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने खड़ी एक ब्रेजा कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा लैपटॉप और धूप के चश्मे से भरा बैग चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में डीडी नंबर 69 के तहत सूचना दर्ज की गई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत ई-एफआईआर संख्या 80093375/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी एएसआई संजय दुबे ने कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल कुलदीप तथा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर विशेष टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतकर्ता से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के व्यवस्थित विश्लेषण के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पंजीकरण संबंधी जानकारी के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ (40 वर्ष), पुत्र लतीफ, निवासी संगम विहार, दिल्ली तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

चोरी का सामान प्राप्त करने वाला भी गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्य आरोपी से पूछताछ के दौरान चोरी किए गए लैपटॉप को ठिकाने लगाने के संबंध में जानकारी जुटाई। मोबाइल नंबर की जांच और मौके पर सत्यापन के बाद पुलिस ने चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले दूसरे आरोपी दिनेश उर्फ देव (22 वर्ष), पुत्र साग्लू, निवासी मदनपुर खादर, दिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने ये सामान किया बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किया गया है: चोरी किया गया लैपटॉप। एक अन्य लैपटॉप। चोरी किए गए धूप के चश्मे।

वारदात में इस्तेमाल की गई यामाहा एफजेड मोटरसाइकिल। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और लगातार जमीनी जांच के समन्वित प्रयासों से इस मामले का खुलासा संभव हो सका। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

दिल्ली नगर निगम ने सेंट्रल नॉर्थ ज़ोन के 08 वार्डों में बैटरी चालित लिटर पिकर मशीनों का परीक्षण संचालन शुरू किया

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आज सेंट्रल नॉर्थ ज़ोन (केशव पुरम ज़ोन) के 08 वार्डों में वैक्यूम आधारित बैटरी चालित लिटर पिकर मशीनों का परीक्षण संचालन शुरू किया। यह पहल दिल्ली में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन लिटर पिकर मशीनों का उद्घाटन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा शहर के सभी 250 वार्डों में कुल 1,000 मशीनें तैनात की जाएंगी। प्रत्येक वार्ड में 04 मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये आधुनिक मशीनें सक्शन होज़ के माध्यम से प्लास्टिक की बोतलें, पेपर कप, रैपर, पत्तियां तथा अन्य हल्के कचरे को एकत्रित करती हैं। इन मशीनों को विशेष रूप से बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, संकरी गलियों एवं व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों की सफाई के लिए तैयार किया गया है, जहां बड़ी यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों की पहुंच कठिन होती है। मशीनों का परीक्षण संचालन संकरे एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। यह पहल दिल्ली नगर निगम की स्वच्छ एवं बेहतर सार्वजनिक स्थलों के निर्माण के लिए आधुनिक, यांत्रिक एवं पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



वाल्मीकि समुदाय ने सेवा और समर्पण से देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने को सुदृढ़ बनाया: विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस समुदाय ने इस राष्ट्र की नैतिक एवं सांस्कृतिक नींव को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसे कभी भी उसकी गरिमा, समानता और उचित सम्मान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को रोशनारा रोड स्थित पारिक भवन में आयोजित स्वच्छता कर्मचारी सम्मान समारोह एवं दीपावली मंगल मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

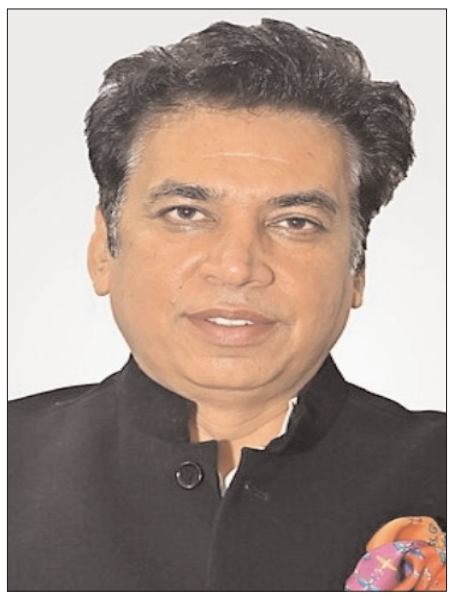
महर्षि वाल्मीकि के भारत की सभ्यतागत विरासत में योगदान को रेखांकित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रामायण ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों को भगवान श्रीराम के जीवन, चरित्र और आदर्शों को समझने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय ने सदियों से अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता जय प्रकाश सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने इसे भारत की साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत में महर्षि वाल्मीकि के चिरस्थायी योगदान की महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जहां दीपावली भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, वहीं महर्षि वाल्मीकि की रामायण ने इन आदर्शों को भारत की सामूहिक चेतना में स्थायी स्थान प्रदान किया है। वाल्मीकि समुदाय के ऐतिहासिक हाशियाकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस समुदाय के सदस्यों ने जिस अपमान, सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा का सामना किया है, वे केवल अतीत के किसी दूरस्थ कालखंड की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी पीड़ाएं हैं, जिन्हें आज भी पीढ़ियां याद करती हैं।

भाजपा का व्यापारी प्रेम सिर्फ दिखावा, गलत नीतियों ने दिल्ली के बाजारों की रौनक छीनी : देवेंद्र यादव

एम.जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा पर व्यापारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एक तरफ खुद को व्यापारियों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी गलत आर्थिक नीतियों और बेतहाशा महंगाई ने दिल्ली के बाजारों की रौनक छीन ली है। खाद्य पदार्थों, दालों, खाद्य तेल, दूध, पेट्रोल और डीजल सहित रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। इसका सीधा असर बाजारों में खरीदारी और व्यापारियों के कारोबार पर पड़ रहा है।

देवेंद्र यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण त्योहारों के सीजन में भी बाजारों में अपेक्षित रौनक दिखाई नहीं दे रही है। लोगों की खरीदारी की क्षमता लगातार घट रही है, जिसके चलते छोटे दुकानदारों और कारोबारियों की बिक्री प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 11.39 प्रतिशत तक पहुंचने से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ-साथ देशभर के करोड़ों व्यापारियों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा समर्थित व्यापारिक संगठनों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दीपावली के दौरान दिल्ली में प्रतिदिन 10 से 12 हजार करोड़ रुपये के कारोबार के अनुमान को आधार बनाकर एक नवंबर को 11 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया। उन्होंने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों की कई व्यापारिक एसोसिएशनों ने इस दावे को खारिज किया है। यादव ने कहा कि यदि रामलीला मैदान के आसपास के बाजार महारैली के दिन खुले रहते, तो रैली में शामिल होने आए लाखों लोग स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते थे। इससे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलता। लेकिन बाजार बंद करवाकर व्यापारियों को संभावित कारोबार से वंचित कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि व्यापारियों की हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा आखिर उनके कारोबार को प्रभावित करने वाले फैसलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया कि भाजपा की महारैली को लेकर व्यापारियों के नुकसान पर राजनीति करने के बजाय सरकार यह बताए कि 30 अक्टूबर 2026 को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ लाल किले से टाउन हॉल तक निकाले गए मार्च के दौरान दिल्ली के व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ। क्या त्योहारों से ठीक पहले का समय व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं था?



देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कई दिनों तक दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मेट्रो की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन बसों को बंद रखने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता व्यापारियों के नुकसान की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण हुए नुकसान पर चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती आमदनी के कारण निम्न, मध्यम और गरीब परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक ओर व्यापारी अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी ओर आम उपभोक्ता महंगाई के कारण जरूरी सामान खरीदने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को केवल व्यापारियों के नुकसान की बात करने के बजाय आम जनता की आर्थिक परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंत में यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकारें महंगाई तथा बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का व्यापारी हितैषी होने का दावा उसकी नीतियों और जमीनी हालात के सामने खोखला साबित हो रहा है।

1984 सिख नरसंहार पीड़ित महिलाओं ने सुनाई आपबीती, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने मंगलवार को तिलक विहार स्थित गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब में आयोजित तीन दिवसीय समागम में अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। इस दौरान माता भागी कौर, कुलजीत कौर, गंगा कौर, अतर कौर, लक्ष्मी कौर, ठाकरी कौर, प्रीति सिंह, जसवीर कौर, परमजीत कौर, मनप्रीत कौर आदि महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। इस मौके पर जोन अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय और पश्चिमी दिल्ली जिले के महामंत्री सरदार चरण जीत सिंह लवली ने भी गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि अर्पित की और सिख नरसंहार में शहीद हुए शहीदों को याद किया। रविवार को शहीद गंज गुरुद्वारे में ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। शहीद हुए परिवारों की महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के संरक्षण में उपद्रवियों ने उनके परिवारों पर बर्बर अत्याचार किए, उनके घर उजाड़े, परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या की और महिलाओं को जीवनभर न भूलने वाला दर्द दिया। पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने कहा कि 1984 का सिख नरसंहार भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, जिसे कांग्रेस कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुला नहीं सकती।

एक नजर

घर में मिला 10 फीट लंबा अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

फरीदाबाद। गांव भाकरी में एक घर के अंदर करीब 10 फीट लंबा अजगर मिलने से परिवार में दहशत फैल गई। अजगर घर की सीढ़ियों के पास उस जगह बैठा था, जिसका इस्तेमाल परिवार के सदस्य नहाने के लिए करते हैं। सोमवार शाम के समय अचानक अजगर पर नजर पड़ते ही परिवार के लोग घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि अजगर का किसी सदस्य से सामना नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को बुलाया गया। देर रात पहुंची टीम ने सावधानी से अजगर को पकडक़र सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। गांव निवासी जीतू ने बताया कि शाम को परिवार के सदस्यों ने घर में अजगर देखा। अचानक इतने बड़े सांप को देखकर वे घबरा गए। इसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी दी गई। सूचना फैलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आसपास के लोग सतर्क हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग को अजगर का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने आबादी के बीच इतने बड़े वन्यजीव के पहुंचने पर चिंता जताई। रात को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग के इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि भाकरी गांव अरावली क्षेत्र के नजदीक बसा है। जंगल से निकलकर अजगर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। टीम ने उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

सीएम फ्लाइंग ने मिठाई बनाने वाली दो जगहों पर की छापेमारी

फरीदाबाद। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एनआईटी -1 और बडखल में मिठाई बनाने वाली दो जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 10 हजार 300 किलो मिठाई तैयार मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ले और बर्फी के कुल तीन सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। टीम को सूचना मिली थी कि शहर में त्योहारों के दौरान मिलावटी रसगुल्ले और गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद डीएसपी विवेक चौधरी के नेतृत्व में टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार के साथ एनआईटी-1 स्थित सोनम फूड फैक्टरी में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फैक्टरी में रसगुल्ले और अन्य मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। मौके पर करीब पांच हजार किलो तैयार रसगुल्ले 20 ड्रम और टब में रखे मिले। संचालक अमरेश ने टीम को एफएसएसएआई का लाइसेंस दिखाया, जो 11 सितंबर 2031 तक वैध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रसगुल्लों के दो सैंपल लिए। इसके बाद टीम ने बडखल क्षेत्र में बुद्धि होटल के पीछे राजकुमार की दुकानों में चल रही बीकानेर बर्फी वाली दुकान पर जांच की। यहां संचालक जितेंद्र सिंह मिला। मौके पर करीब 5300 किलो बीकानेरी बर्फी रखी हुई थी। संचालक ने टीम को वैध एफएसएसएआई लाइसेंस दिखाया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बर्फी का एक सैंपल लिया। तीनों सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों जगहों पर मिलावट की पुष्टि नहीं हुई है।

एनसीआर में पांच से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रहेगी रोक

नूंह। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एहतियाती कदम उठाए हैं। आयोग के निर्देशों के तहत 5 से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करते हुए जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उपायुक्त ने बताया कि सीएक्यूएम के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में धूल पैदा करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि, इस प्रतिबंध से रेलवे, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पतालों, जलापूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़े कार्यों को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली प्रेषण, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उनके नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाए।

गुरुग्रामः विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में उद्योग जगत निभाए भूमिकाः राव नरबीर सिंह

गुरुग्राम। हरियाणा के उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने और प्रदेश के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से मंगलवार को गुरुग्राम में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने होटल ग्रैंड हयात में लेवरेजिंग एफटीए-आउटरीच प्रोग्राम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अगले पांच वर्षों में प्रदेश का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा। कार्यशाला में भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से हरियाणा के उद्योगों, एमएसएमई और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों तथा निर्यात विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा की गई। कार्यशाला का आयोजन हरियाणा सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निदेशालय द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य



विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) तथा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के कमिश्नर एवं सचिव डॉ. अमित के. अग्रवाल, गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर रवि प्रकाश गुप्ता, हरियाणा एमएसएमई एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. यश गर्ग, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में निदेशक डॉ. गरिमा मित्तल तथा एचएसआईआईडीसी के एमडी विनय प्रताप सिंह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार विशेषज्ञ और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हत्या के मामले में वांछित दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना जेवर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे दो बदमाशों को आज सुबह को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी है। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि आज तड़के थाना जेवर पुलिस झाझर रोड के पावर हाउस के पास बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिए।

जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। उन्होंने बताया कि पीछा करके पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अपने आपको पुलिस से घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली शेरू उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र युसूफ निवासी मोहल्ला व्यापारियन कस्बा जहांगीरपुर तथा मौसीम पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला पठान टोला कस्बा पहासू जनपद बुलंदशहर के पैर में लगी है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो अवैध पिस्टल , कारतूस आदि बरामद किया है। उन्होंने बताया कि दोनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि इन बदमाशों ने 7 अक्टूबर की रात को इमरान (36) की कस्बा जहांगीरपुर के भरे बाजार में ताबड़तोड़ गोली चलाकर सरेआम हत्या कर दी थी। इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई।

गुरुग्राम नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की सिफारिश

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन, रखरखाव एवं हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत मेजर पेनल्टी कार्यवाही शुरू करने के लिए चार्जशीट जारी करने की सिफारिश की है।

इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के आयुक्त व सचिव को पत्र भेजा गया है। मामला नगर निगम की मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित छह माह के दो अनुबंधों के दौरान मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं से जुड़ा है। निगम द्वारा 20 मशीनों के लिए 26 सितंबर 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था, जबकि पांच मशीनों के लिए 12 अगस्त 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था। संबंधित अवधि में कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण इस कार्य के प्रभारी थे। निगमायुक्त द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त निगमायुक्त यश जलुका को सौंपी गई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को जांच की तथा 28 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में संबंधित कार्यकारी अभियंता और एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जांच रिपोर्ट में मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में पर्याप्त तकनीकी सत्यापन नहीं किए जाने, मशीनों एवं उनके कलपुर्जों की वास्तविक स्थिति का उचित लिखित रिकॉर्ड और प्रमाणन उपलब्ध नहीं होने तथा निगम की संपत्तियों की सुरक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी नहीं किए जाने जैसी कमियां सामने आईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व एजेंसी जे.के. कॉन्ट्रैक्टर से मशीनों की मरम्मत लागत की वसूली तथा अनुबंध के तहत निर्धारित पेनल्टी लगाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। जांच के दौरान नई एजेंसी राधा कृष्ण सोसाइटी लिमिटेड की जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। आरएफपी की शर्त संख्या 3.6 के अनुसार एजेंसी को बोली लगाने से पहले मशीनों का निरीक्षण करना तथा उन्हें जैसी हैं, जहां हैं के आधार पर स्वीकार करना था। वहीं शर्त संख्या 5(डी) के तहत बड़ी मरम्मत सात दिनों के भीतर पूरी की जानी थी।

सड़क हादसों में दो वर्षीय मासूम समेत चार की मौत

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। नोएडा में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए विभिन्न सड़क हादसों में एक दो वर्षीय मासूम बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई। सभी घटनाओं में पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। थाना सेक्टर 142 के प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले शनि मोदी अपने परिवार के साथ शाहदरा गांव में रहते हैं। उनका दो वर्षीय बेटा शिवराज मंगलवार सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी वहां से पानी की सप्लाई करने वाले पिकअप वाहन टक्कर मरता हुआ गुजर गया। बच्चे को गंभीर हालत में उपचार के लिए फेलिक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। जबकि चालक फरार हो गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

थाना सेक्टर 20 के प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि महेश शर्मा (46) पुत्र कृष्ण देव शर्मा मूलरुप से जनपद समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे। यहां वह निठारी गांव में रहकर मजदूरी का काम करते थे। बीती रात सोमवार को वह पैदल गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन चालक ने वाहन से उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान



उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी तरह थाना रबूपुरा के प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक सड़क हादसे में अजय सोलंकी (39) पुत्र टीकम सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। वहीं थाना एक्सप्रेसवे के प्रभारी अमित खारी ने बताया कि बीती रात सोमवार को थाना क्षेत्र अंगर्तत एक सड़क हादसे में हनीफ (31) की मौत हो गई है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुरुग्रामः मानेसर नगर निगम क्षेत्र में पांच नवंबर से निर्माण-तोड़फोड़ पर पूर्ण रोक

गुरुग्राम। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन(सीएक्यूएम) के आदेशानुसार नगर निगम मानेसर क्षेत्र में ग्रैप-2 की पालना शुरू कर दी गई है। पांच नवंबर से आगामी आदेशों तक निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण और तोडफोड़ कार्य पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।

नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिन स्थानों पर अभी निर्माण कार्य चल रहें हैं, वहां पालना सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक इंतजाम किए जाएं। निर्माण सामग्री जैसे ईंट, रोड़ी, बजरी, रेता को पूरी तरह ढककर रखा जाए, ताकि हवा चलने पर धूल न उड़े। साइटों पर लगातार पानी का छिडक़ाव किया जाए। जरूरत के अनुसार एंटी स्मॉग गन का उपयोग करके भी पानी का छिडकाव किया जा सकता है। आयुक्त ने निर्देश किए कि निर्माणाधीन साइटों को हरी चादर या अन्य उपयुक्त कपड़े से ढका जाए। इससे निर्माण स्थल से उडऩे वाली धूल को काफी हद तक रोका जा सकेगा। आयुक्त ने आम नागरिकों, बिल्डरों, आरडब्ल्यूए, ठेकेदारों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों से अपील की है कि जनहित में सीएक्यूएम के आदेशों की पूरी



ईमानदारी से पालना करें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल सरकार या सरकारी एजेंसियों की समस्या नहीं है, इससे बच्चों, बुजुर्गों, श्वास रोगियों सहित सभी जीवों के स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ता है। इसलिए आमजन की जिम्मेदारी बनती है कि वह धूल फैलाने वाली गतिविधियों से बचे और निर्माण साइटों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियम तोडऩे वालों के चालान किए जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। निगम की टीमें निगम क्षेत्र में नियमित सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान निर्माण साइटों पर सामग्री ढकने, पानी का छिडक़ाव, हरी चादर और धूल नियंत्रण की जांच भी की जा रही है।

ऋषिकेश घूमकर लौटे इंजीनियर की बाथटब में मिली लाश

गुरुग्राम। सेक्टर-53 स्थित एक होटल के कमरे में यूके से भारत आए एक इंजीनियर का शव संदिग्ध हालत में बाथटब में मिला है। मृतक हाल ही में ऋषिकेश घूमकर लौटा था और सोमवार रात गुरुग्राम में रुका था। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

मृतक की पहचान प्रांजिल पाठक (35) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा की ओल्ड ईदगाह कॉलोनी का रहने वाला था और यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर में रहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रांजिल हाल ही में यूके से भारत आया था। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में छुट्टियां मनाने के बाद सोमवार को दिल्ली लौटा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दोस्त को फ्लाइट में छोडऩे के बाद उसने रात बिताने के लिए सेक्टर-53 स्थित ओरसम होटल में कमरा नंबर 302 बुक किया था। रात करीब 8 बजे होटल स्टाफ को अनहोनी का शक हुआ तो कमरे की जांच की गई।

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा व आत्मनिर्भरता की भावना सराहनीयः एसीयूटी अमितेज पांगती

नूंह। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छपेड़ा में दिवाली हुनर मेला मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसीयूटी अमितेज पांगती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेले में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हस्तशिल्प उत्पादों, मिट्टी के दीयों, पर्यावरण अनुकूल सजावटी वस्तुओं, रंगोली डिजाइनों और गृह सज्जा सामग्री की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई।

मुख्य अतिथि ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर विद्यार्थियों के हुनर और मेहनत की सराहना की। एसीयूटी अमितेज पांगती ने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और रचनात्मक सोच से आकर्षक उत्पाद तैयार किए हैं। इस प्रकार के आयोजन बच्चों में आत्मनिर्भरता, नवाचार और व्यावहारिक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को निखारना और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि मेले में प्रदर्शित उत्पाद विद्यार्थियों की कलात्मक क्षमता के साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी जागरूकता को भी दर्शाते हैं। मेले के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत, लोकनृत्य, कविताओं और लघु नाटिकाओं के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। इससे पहले विद्यालय की प्राचार्या प्रोमिला कुमारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए मेले के आयोजन के उद्देश्य और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

गुरुग्राम में लगातार धंस रही सड़कें, क्या रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं शासन-प्रशासनः पंकज डावर

गुरुग्राम,एजेंसी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने गुडग़ांव में लगातार सडक़ें धंसने की घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुडग़ांव में सडक़ें धंसने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है सरकार सडक़ें धंसने का ही रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। पंकज डावर ने विशेष रूप से गुरुग्राम-सोहना हाइवे का जिक्र करते हुए कहा कि यह हाइवे भ्रष्टाचार की जीती-जागती मिसाल बन गया है। करोड़ों रुपये की लागत से बना यह हाइवे सातवीं बार धंस गया है।

उन्होंने कहा कि एक ही हाइवे का एक ही हिस्सा सात बार धंस जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या हो सकता है। हर बार सरकार लीपापोती करती है, मिट्टी डालकर गड्ढा भर दिया जाता है, फिर कुछ महीनों बाद वही सडक़ फिर धंस जाती है। जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम-सोहना हाइवे से हजारों लोग रोजाना सोहना, नूंह और अलवर की तरफ आते-जाते हैं। जब से यह हाइवे बना है, तब से यह हादसों का हाइवे बन गया है।

कभी सर्विस लेन धंस जाती है तो कभी मुख्य सडक़। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक से यह सडक़ बनाई गई है जो हर बारिश में या बिना बारिश के ही बैठ जाती है। पंकज डावर ने कहा कि सडक़ें धंसने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। अगर पहली बार सडक़ धंसने पर ही ठेकेदार पर कार्रवाई होती, उसकी सिक्योरिटी जब्त होती और ब्लैकलिस्ट किया जाता, तो आज सातवीं बार यह नौबत नहीं आती। सरकार में बैठे लोगों की ठेकेदारों से मिलीभगत है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। डावर ने दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे-48 का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एनएच-48 पर बने फ्लाईओवरों की हालत भी खस्ता है। पिछले दो साल से इन फ्लाईओवरों से कंक्रीट के टुकड़े गिर रहे हैं।

एसटीएफ ने झज्जर में कारतूसों का बड़ा जखीरा पकड़ा

गुरुग्राम। एसटीएफ बिहार से मिली सूचना के आधार पर हरियाणा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को झज्जर में 25 हजार जिंदा कारतूसों के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 3 नवंबर 2026 की सुबह एसटीएफ की रोहतक टीम ने जिला झज्जर के रोहद में त्रिवेणी ढाबे के सामने सडक़ किनारे खड़ी दो गाडियों टाटा हैरियर व हुंडई ऑरा की तलाशी ली। तलाशी के दौरान टाटा हैरियर से केएफ 7.65 और बीएमएम केएफ बोर के 24,400 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गाड़ी में तीन लोग सवार थे। वहीं हुंडई ऑरा से बीएमएम केएफ अंकित 600 जिंदा कारतूस मिले। इस गाड़ी में दो लोग सवार थे। कुल मिलाकर 25,000 कारतूस बरामद किए गए। मौके से आठ मोबाइल फोन भी बरामद हुए।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान (49), निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, आसिम रईस (33) निवासी बदायूं, सबलू खान (32) निवासी बदायूं, अरबाज अली (27) निवासी बदायूं, जीनत (33) बदायूं के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से बरामद गाडियां, कारतूस और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। कारतूसों के संबंध में आरोपी



कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाए। इस संबंध में थाना आसोदा जिला झज्जर में आर्म्स एक्ट में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही एसटीएफ बिहार पुलिस ने भोजपुर जिले में इसी तरह के मामले में लल्टू नामक व्यक्ति को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था और करीब 20,000 कारतूस बरामद किए थे। आरोप है कि लल्टू, अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान के निकट संपर्क में था और उसी से कारतूस प्राप्त किए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अफीफुद्दीन बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बदायूं गन हाउस चलाता है। वह सिरसा गया था और वहां के निवासी विजय गोयल से कारतूसों का यह बड़ा जखीरा प्राप्त किया था। विजय गोयल सिरसा स्थित महक गन हाउस का मालिक है। कारतूसों के स्रोत और गन हाउसों के वितरण नेटवर्क का पता लगाने के लिए एसटीएफ बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के समन्वय से आगे की जांच की जा रही है।

इन 55 हजार मौतों की आशंका पर चर्चा तक नहीं

योगेंद्र योगी



देश में सत्तारुढ़ राजनीतिक दलों के लिए मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव चिंता का विषय नहीं है। ऐसे परिवर्तनों की चपेट में आने वाले गरीब होते हैं। इनकी आवाज सुनने वाली देश में कोई सरकार नहीं है। सिर्फ इनकी सुनवाई के दावे किए जाते हैं, जबकि पर्यावरण के प्रभावों से बचाने के इंतजामों पर चर्चा तक नहीं होती है। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के जारी किया गए नक्शे आंकड़े काफी डराने वाले हैं। अलनीनो के प्रभाव से उत्पन्न गर्मी से भारत में जहां 55,200 लोगों की मौत होने की आशंका है। इसके बावजूद यह मुद्दा देश के सत्तारुढ़ दलों के चिंता का सबब नहीं है। अल नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर (अल नीनो के कारण गर्मी से होने वाली मौतों का ट्रैकर) नामक इस भयावह नक्शे के मुताबिक नक्शे के अनुसार जून 2026 में शुरू होने वाली इस घटना से मार्च 2027 तक गर्मी के कारण 857,400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा एक महीने पहले लगाए गए अनुमान से 350,000 ज्यादा है। इनमें से एक-तिहाई मौतें नाइजीरिया, भारत और ब्राजील में होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जून के बाद से 'अल नीनो' के कारण 484,500 अतिरिक्त मौतें हुई हैं। इसके कुछ असर इस तरह दिखे हैं। इंडोनेशिया में जंगलों में आग लगना, भारत में अहम मानसूनी बारिश का न होना और मध्य अमेरिका में सूखा पड़ना। अल नीनो की वजह से इन नौ महीनों की इस अवधि के अनुमान में लगाई गई आधी से ज्यादा अतिरिक्त मौतें अगले छह महीनों के भीतर होने की आशंका है और भारत पर इसका भयावह रूप देखने को मिल सकता है। इतिहास के पन्नों में 1877-1878 के 'सुपर अल नीनो' को सबसे विनाशकारी मौसमी घटनाओं में गिना जाता है। उस दौरान इसके प्रभाव से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ा था। लगातार बारिश न होने के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। इतिहास में इसे 'ग्रेट फेमाइन' के रूप में जाना जाता है। इस अकाल के कारण भुखमरी और बीमारियों से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की सतह के तापमान में अत्यधिक वृद्धि उस सदी के सबसे बड़े जलवायु संकट का कारण बनी थी। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के सह-संस्थापक और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के मिल्टन फ्रीडमैन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर, माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा है कि सुपर अलनीनो पर हमारा शोध नई पूर्वानुमान क्षमताओं का इस्तेमाल करके हमारे सामने मौजूद सबसे जरूरी सवालों में से एक का जवाब देता है। अत्यधिक गर्मी के कारण कहां लोगों की जान जाने का खतरा है? अल नीनो एक मौसमी घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। यह अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन का गर्म चरण है।

यह एक प्राकृतिक मौसमी पैटर्न है जो दुनिया भर में वायुमंडलीय परिसंचरण, हवाओं के तंत्र और बारिश के वितरण को प्रभावित करता है। इंडोनेशिया में धधकती भयानक जंगलों की आग से लेकर प्रशांत महासागर में तूफानों की असामान्य सक्रियता तक अल नीनो का असर दुनिया के लगभग हर कोने में देखने को मिल रहा है। इस असामान्य मौसमी गतिविधि के कारण आने वाले समय में दुनिया भर में अलग-अलग क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और अनिश्चित बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा काफी बढ़ गया है। दिसंबर में अल नीनो अपने चरम पर पहुंच सकता है, जिसके प्रभाव से नवंबर से जनवरी के बीच भारत में सामान्य से कम सर्दी पड़ने की संभावना है। हालांकि उत्तरी हिस्से में ठंड की तीव्रता पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं पर निर्भर करती है। इस दौरान दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार में कभी-कभी शीतलहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। मैदानों में तापमान कुछ समय के लिए गिर सकता है। फिर भी मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस बार लंबे समय तक कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका काफी कमजोर है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार नवंबर से जनवरी के दौरान प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति और मजबूत हो सकती है। कई जलवायु माडल संकेत दे रहे हैं कि दिसंबर में यह चरम पर पहुंच सकता है। समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन का असर मौसम पर पड़ता है। हालांकि इसका असर देश के सभी हिस्सों में एक समान नहीं होगा। भारत में मानसून के दौरान 13 प्रतिशत कम बारिश होने के बाद, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मौसमी घटना सर्दियों में तापमान बढ़ाएगी, क्या ये बारिश के पैटर्न को बिगाड़ेगी और क्या कृषि पर दबाव बढ़ाएगी? भारत के मामले में अल नीनो पर कड़ी नजर रखी जाती है, क्योंकि आमतौर पर इसके कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने का खतरा बढ़ जाता है। बीते मानसूनी सीजन में भारत के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का असमान वितरण देखने को मिला। मध्य भारत में तो लगभग सामान्य बारिश हुई, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जिसे असाधारण सूखा माना जा सकता है।

वहीं दक्षिणी राज्यों में भी औसत से 24 प्रतिशत कम बारिश हुई।

अल नीनो के और मजबूत होने से भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी हो सकती है, जिससे जल संसाधनों और कृषि पर दबाव बढ़ सकता है। आने वाले महीनों में अल नीनो का बढ़ता असर भारत के जल संसाधनों, कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। सरकार और कृषि विभागों को किसानों के लिए समय पर एडवाइजरी जारी करने, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने और जलाशयों में पानी के सही प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि संभावित खाद्य संकट से बचा जा सके। सवाल यही है क्या देश के सत्तारुढ़ राजनीतिक दलों ने अलनीनो के प्रभाव से होने वाली मौतें और पेयजल तथा कृषि की चुनौतियों से निपटने के कोई इंतजाम किए हैं। दरअसल इसकी चर्चा तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं की हैं। करीब 50 हजार लोगों की संभावित मौतों का यह मसला देश के नेताओं के लिए चिंता की बात नहीं है। ये मौतें अचानक नहीं होंगी। गर्मी के प्रभाव और पानी की कमी और दूषित पेयजल की मजबूरी से होने वाली मौतें धीमी मौत् होती है। यही वजह है कि नेताओं को इसकी चिंता नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि ऐसी मौतों का मसला वोट नहीं दिला सकता। इसी वजह से हर साल पर्यावरण परिवर्तन से होने वाली मौतें कभी भी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं की जाती हैं।

जब पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में हुई इस हृदयविदारक घटना का वीडियो देखा तो मन बेहद विचलित हो उठा। आरोपी छात्र बच्ची को एक खाली कक्षा में ले गया, वहां उसके बाल पकड़कर घसीटा, बेंच पर सिर पटका, लातें मारी तथा ईंट, पत्थर और गमले से उसके सिर तथा चेहरे पर बार-बार प्रहार किए। करीब 96 सेकेंड तक चली इस हिंसा का दृश्य कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हमला करने वाला कोई वयस्क अपराधी नहीं बल्कि 8 वर्ष का बच्चा है। यह घटना जितनी पीड़ित बच्ची के लिए भयावह है, उतनी ही उस बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। आखिर इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के भीतर इतनी आक्रामकता कहां से आती है? क्या उसने हिंसा को सामान्य व्यवहार मान लिया है? क्या वह किसी के दर्द और असहायता को महसूस करने की क्षमता खो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हमारे घरों, स्कूलों और समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि बचपन की भाषा में प्रेम और संवेदना की जगह हिंसा प्रवेश करती जा रही है? उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह बच्ची के असहाय हो जाने के बाद भी हमला जारी रहने की बात सामने आई है, वह सामान्य बाल-सुलभ झगड़े से कहीं अधिक गंभीर है। इस घटना ने एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है कि आखिर बच्चों के मन में हिंसा के बीज कौन बो रहा है?

आखिर कौन बो रहा है बच्चों के मन में हिंसा के बीज?

योगेश कुमार गोयल

बचपन को मासूमियत, निश्छलता, संवेदनशीलता और खिलखिलाती मुस्कान का पर्याय माना जाता है। बच्चों के हाथों में खिलौने अच्छे लगते हैं, पत्थर और ईंटें नहीं, उनकी आंखों में सपने अच्छे लगते हैं, किसी के प्रति नफरत और हिंसा नहीं। लेकिन जब 8-10 वर्ष की उम्र के बच्चे भी किसी दूसरे मासूम की जान लेने पर उतारू हो जाएं, तब सवाल केवल एक बच्चे के असामान्य व्यवहार का नहीं रह जाता बल्कि पूरे सामाजिक परिवेश, पारिवारिक संस्कारों, शिक्षा व्यवस्था और हमारी बदलती जीवनशैली का हो जाता है। हरियाणा के पंचकूला में छह साल की विशेष आवश्यकता वाली बच्ची पर तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र द्वारा किया गया बर्बर हमला इसी भयावह वास्तविकता का आईना है। जब पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में हुई इस हृदयविदारक घटना का वीडियो देखा तो मन बेहद विचलित हो उठा। आरोपी छात्र बच्ची को एक खाली कक्षा में ले गया, वहां उसके बाल पकड़कर घसीटा, बेंच पर सिर पटका, लातें मारी तथा ईंट, पत्थर और गमले से उसके सिर तथा चेहरे पर बार-बार प्रहार किए। करीब 96 सेकेंड तक चली इस हिंसा का दृश्य कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हमला करने वाला कोई वयस्क अपराधी नहीं बल्कि 8 वर्ष का बच्चा है। यह घटना जितनी पीड़ित बच्ची के लिए भयावह है, उतनी ही उस बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। आखिर इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के भीतर इतनी आक्रामकता कहां से आती है? क्या उसने हिंसा को सामान्य व्यवहार मान लिया है? क्या वह किसी के दर्द और असहायता को महसूस करने की क्षमता खो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हमारे घरों, स्कूलों और समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि बचपन की भाषा में प्रेम और संवेदना की जगह हिंसा प्रवेश करती जा रही है? उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह बच्ची के असहाय हो जाने के बाद भी हमला जारी रहने की बात सामने आई है, वह सामान्य बाल-सुलभ झगड़े से कहीं अधिक गंभीर है।

इस घटना ने एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है कि आखिर बच्चों के मन में हिंसा के बीज कौन बो रहा है? बच्चों और किशोरों में हिंसक व्यवहार का कोई एक कारण नहीं होता। परिवार में हिंसा देखना, कठोर अथवा असंगत अनुशासन, भावनात्मक उपेक्षा, कमजोर अभिभावकीय निगरानी, साथियों का दबाव, सामाजिक अलगाव और व्यवहार पर नियंत्रण की कठिनाइयां इसके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सवाल परिवारों से है। आज अनेक घरों में बच्चों को महंगे खिलौने, स्मार्टफोन, टैबलेट और मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं लेकिन उनके साथ बैठकर बातचीत करने, उनकी भावनाएं समझने और उनके व्यवहार को दिशा देने का समय लगातार कम होता जा रहा है। माता-पिता अपनी व्यस्तताओं में उलझे हैं और कई बार बच्चे अपनी भावनात्मक उलझनों के साथ अकेले रह जाते हैं। घर में माता-पिता के झगड़े, गाली-गलौज, मारपीट, अपमानजनक भाषा और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक प्रतिक्रिया देखने वाले बच्चों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बच्चा वही सीखता है जो अपने आसपास बार-बार देखता है। यदि घर में समस्या का समाधान संवाद से नहीं बल्कि चीखने, धमकाने और हाथ उठाने से होता है तो उसके लिए हिंसा धीरे-धीरे व्यवहार का स्वीकार्य तरीका बन सकती है। दूसरा बड़ा सवाल डिजिटल दुनिया का है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने बच्चों के सामने ज्ञान और मनोरंजन के असंख्य अवसर खोले हैं लेकिन इसी दुनिया में हिंसक वीडियो, मारधाड़ वाले खेल, अपमानजनक सामग्री और आक्रामक व्यवहार को महिमामंडित करने वाले दृश्य भी मौजूद हैं। समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब बच्चा बिना किसी निगरानी के घंटों ऐसी सामग्री देखता है और उसे यह समझाने वाला कोई नहीं होता कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली हिंसा वास्तविक जीवन में किसी के शरीर, मन और अस्तित्व को कितनी गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरी चिंता बच्चों में संवेदनशीलता और सहानुभूति के विकास की है। आज हम बच्चों को प्रतियोगिता में आगे निकलना, जीतना और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना तो सिखा रहे हैं लेकिन हार स्वीकार करना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, कमजोर की मदद करना और क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना सिखा रहे हैं? क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा केवल पाठ्य-पुस्तकों तक सिमट गई है? क्या बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि किसी को चोट पहुंचाना बहादुरी नहीं, कमजोरी है? किसी दूसरे की पीड़ा देखकर मन में करुणा पैदा होना ही मानवीय संवेदना का आधार है। यदि यही संवेदना विकसित नहीं होगी तो शिक्षा की बड़ी-बड़ी डिग्रियां भी सभ्य समाज की गारंटी नहीं बन सकतीं। यहां स्कूलों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।



पंचकूला की घटना ने सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी और वास्तविक निगरानी के बीच के अंतर को उजागर किया है। कैमरे लगे होना सुरक्षा नहीं है, उनकी सतत निगरानी, समय पर हस्तक्षेप और जवाबदेही ही सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सवाल है कि एक छह साल की बच्ची स्कूल परिसर में एक अन्य छात्र के साथ ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गई, जहां उस पर लगातार हमला होता रहा और किसी शिक्षक या कर्मचारी को समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिली? यदि स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, एक शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी अथवा ड्यूटी व्यवस्था में कोई खामी थी तो यह भी जांच का विषय है। यह पहली घटना नहीं है, जब स्कूलों में बच्चों के बीच हिंसा ने पूरे देश को झकझोरा हो। वर्ष 2017 में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या, 2018 में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में चाकूबाजी, 2019 में तमिलनाडु के कोडईकनाल में क्रिकेट विवाद के बाद छात्र की हत्या, 2021 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छात्र की चाकू मारकर हत्या, 2025 में अहमदाबाद में छात्र की हत्या और 2026 में सूरत में स्कूल परिसर में चाकूबाजी जैसी घटनाएं अलग-अलग समय पर सामने आ चुकी हैं। इन सभी मामलों की परिस्थितियां अलग हैं लेकिन एक बात समान है कि स्कूल, जिन्हें बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, वहां भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब समय आ गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग स्कूलों की सुरक्षा को केवल औपचारिक निरीक्षण और कागजी दिशा-निर्देशों तक सीमित न रखें। प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, प्रशिक्षित काउंसलर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित सहयोगी कर्मचारी, संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों के व्यवहार में अचानक आक्रामकता, दूसरों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति, क्रोध पर नियंत्रण न रहना, पश्चाताप का अभाव, जानवरों अथवा कमजोर बच्चों के प्रति क्रूरता जैसे संकेतों को सामान्य शरारत समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देना और प्रेम के साथ स्पष्ट अनुशासन सिखाना जरूरी है। खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियां, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियां भी उनमें सहयोग, धैर्य और सहानुभूति विकसित कर सकती हैं। पंचकूला की घटना हमें एक कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है कि बच्चों का भविष्य केवल अच्छे स्कूल, महंगी शिक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं से सुरक्षित नहीं हो सकता। उसके लिए अच्छे संस्कार, भावनात्मक सुरक्षा, मानवीय संवेदना और जिम्मेदार अभिभावक भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस समाज में बच्चे दूसरों का दर्द महसूस करना भूलने लगें, वहां विकास के तमाम दावे खोखले साबित होने लगते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि पंचकूला में एक 8 वर्षीय बच्चे ने 6 साल की बच्ची पर हमला क्यों किया बल्कि यह है कि हम ऐसी नौबत आने से पहले क्या कर रहे थे और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या करेंगे? जिस उम्र में बच्चों को अक्षर ज्ञान, दोस्ती, खेल और मानवीय रिश्तों का अर्थ समझना चाहिए, उस उम्र में यदि उनके हाथों में ईंट और पत्थर दिखाई देने लगें तो यह केवल एक परिवार या स्कूल की विफलता नहीं बल्कि हमारी सामूहिक सामाजिक चेतना की पराजय है। हमें तय करना होगा कि बच्चों को केवल प्रतियोगिता में जीतना सिखाना है या इंसानियत के साथ जीना भी क्योंकि बचपन यदि हिंसक हो गया तो भविष्य सभ्य कैसे होगा? और यदि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं तो फिर उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी कौन देगा?

विचार

जांच से संरक्षण और जांच एजेंसियों की स्वायत्तता के बीच संवैधानिक संतुलन

अभिषेक शुक्ल

विनीत नारायण से तेजाराम तक का सफर बताता है कि ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को संरक्षण देना जितना जरूरी है, भ्रष्टाचार की जांच को निर्बाध रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धारा 17ए पर सर्वोच्च न्यायालय की ताजा व्याख्या ने इसी संवैधानिक बहस को नई दिशा दी है। कल्पना कीजिए कि एक सरकारी अधिकारी किसी जनहितकारी योजना के क्रियान्वयन, किसी कर्मचारी की पदोन्नति अथवा किसी सार्वजनिक परियोजना के संबंध में निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। यदि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय के बाद अधिकारी को आपराधिक जांच का भय सताने लगे तो वह कठिन और महत्वपूर्ण फैसले लेने से बच सकता है। प्रशासन में निर्णयहीनता पैदा हो सकती है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यदि किसी अधिकारी को केवल अपने सरकारी पद के कारण जांच से पहले विशेष अनुमति का कवच मिल जाए तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सामने यही दोहरी चुनौती है- ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक जांच और उत्पीड़न से बचाना तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए इसी चुनौती के बीच खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2026 को तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य में इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्णयों को संरक्षण देने वाली यह व्यवस्था रिश्वतखोरी जैसे स्वतंत्र आपराधिक कृत्यों के लिए ढाल नहीं बन सकती।

इस बहस की जड़ें लगभग तीन दशक पुरानी हैं। वर्ष 1997 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को महत्वपूर्ण माना था। जैन हवाला प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उस व्यवस्था को समाप्त किया, जिसके तहत कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक थी। यह व्यवस्था 'सिंगल डायरेक्टिव' के नाम से जानी जाती थी। इस निर्णय का व्यापक संदेश था कि भ्रष्टाचार की जांच में किसी अधिकारी का पद उसे विशेष छूट नहीं दे सकता। इसके बाद भी विधायी स्तर पर पूर्व अनुमति की व्यवस्था लौटती रही। वर्ष 2003 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई। इसके तहत संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ मामलों में जांच से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। वर्ष 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रावधान को अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने माना कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में अधिकारियों के पद के आधार पर अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। हालांकि, वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17ए जोड़ी गई। इसके तहत किसी लोकसेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई संस्तुति अथवा निर्णय से संबंधित कथित अपराध की जांच या पूछताछ शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक कर दी गई। इसके पीछे तर्क था कि अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण शिकायतों और अनावश्यक जांच के भय से मुक्त रखा जाए, ताकि वे स्वतंत्र होकर प्रशासनिक निर्णय ले सकें। लेकिन क्या यह प्रावधान जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को सीमित करता है? क्या सरकार की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू होने से पहले ही एक अवरोध खड़ा कर सकती है? यही प्रश्न जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचा। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ मामले में 13 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के बीच मतभेद के कारण विभाजित निर्णय आया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने धारा 17ए को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त किए जाने योग्य बताया। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने इसे सीमित अर्थ में बनाए रखने की राय दी और सरकार की अनुमति से पहले लोकपाल अथवा लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्था द्वारा परीक्षण की व्यवस्था पर बल दिया। दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मत के कारण इस संवैधानिक प्रश्न को आगे विचार के लिए बड़ी पीठ के समक्ष भेजे जाने की प्रक्रिया निर्धारित हुई। इस प्रकार धारा 17ए की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय का प्रश्न अभी अलग से विचाराधीन है।

एक नजर

कला व संगीत हमारी संस्कृति की आत्मा है : डीईओ



सुपौल। टीसी हाईस्कूल के सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय कला उत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ। जिला समग्र शिक्षा विभाग (एसएसए) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डीईओ ने कहा कि कला और संगीत हमारी संस्कृति की आत्मा हैं। कला उत्सव न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच है, बल्कि अपनी कला, परंपरा और लोकसंस्कृति को सहेजने और संजोने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए निर्णायक मंडल को निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। जिला संयोजक नंदलाल पासवान ने बताया कि प्रतिभागियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस बार प्रतियोगिता दो दिनों तक आयोजित की जा रही है। पहले दिन शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, समूह लोकगीत, वादन सहित कुल सात विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। वहीं, बुधवार को शेष पांच विधाओं की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि कुल 12 विधाओं में से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को राज्यस्तरीय कला उत्सव में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में जिले के संगीत एवं कला शिक्षक रामू अवस्थी, मुकेश मिलन, कन्हैया कुमार कन्हैया, कुंदन कुमार सिंह, हेमकांत कुमार हंस, रौशन कुमार, प्रमोद कुमार पोद्दार, शम्भू कुमार मंडल, सुमित कुमार सिंह, रचना कुमारी, रितु कुमारी, किरण मिश्र, सुमन कुमार राय, ललित कुमार, अंगद कुमार एवं सुदर्शन कुमार सिंह शामिल रहे।

बीआरसी कॉर्डिनेटर को गोली मारने का आरोपित महताब गिरफ्तार, हथियार और दो कारतूस बरामद



अररिया। जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बीआरसी भवन में कॉर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हफसूल वार्ड संख्या 12 निवासी 26 वर्षीय उमर फारूख पिता अब्दूल रहमान को कल सोमवार की रात को गोली मारकर घायल कर दिया गया था।मामले में जोकीहाट थाना में कांड संख्या 437/26, दिनांक 03.11.2026 सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। घटना के संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी जितेन्द्र कुमार द्वारा कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा घटना के संदर्भ में तकनीकी तथा मानवीय सूचना के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त जोकीहाट के चकई निवासी मो. महताब आलम को गिरफ्तार किया गया तथा इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार देशी पिस्टल के साथ दो कारतूस को बरामद की गई। छापामारी दल में जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा,एसआई रजनीकांत कुमार,पंकज कुमार और सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। जानकारी सदर एसडीपीओ सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार शाम को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।उधर घायल उमर का पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है,जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

बिहार में किसी भी राजपूत को किसी नेता पर इतना भरोसा नहीं है कि उनके कहने मात्र से कोई दूसरा उम्मीदवारी छोड़ दे : रूडी

सारण। सारण जिला में दिशा समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बेबाक अंदाज में कई सियासी मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) समर्थित जदयू प्रत्याशी की हार पर दुख जताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी राजपूत को किसी नेता पर इतना भरोसा नहीं है कि उनके कहने मात्र से कोई दूसरा उम्मीदवारी छोड़ दे। कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए जाने पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उनके कहने पर कोई उम्मीदवार अपनी दावेदारी छोड़ सकता था, तो उन्होंने दो-टूक अंदाज में उन्होंने कहा कि आज बिहार में किसी भी राजपूत को किसी नेता पर इतना भरोसा नहीं है कि उनके कहने मात्र से कोई दूसरा उम्मीदवारी छोड़ दे। मेरे या किसी के कहने पर कोई पीछे हट जाए, ऐसी परिस्थिति फिलहाल बिहार में नजर नहीं आती है। यह पूरी तरह से भाजपा तय करती है कि किसे और कब महत्व देना है। सारण सांसद ने राजग समर्थित जदयू उम्मीदवार की हार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि तमाम कोशिशों और गठबंधन द्वारा पूरी ताकत झोंकने के बावजूद प्रत्याशी चुनाव जीतने में असफल रहे। उन्होंने माना कि इस परिणाम से कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसके साथ ही रूडी ने राजग की एकजुटता पर जोर देते हुए विश्वास जताया कि बिहार में गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। यदि भविष्य में कोई मतभेद उभरकर सामने आते भी हैं, तो गठबंधन के वरिष्ठ नेता आपसी सौहार्द से उसका समाधान निकाल लेंगे। वहीं, एक निर्दलीय उम्मीदवार के भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि यह संगठन का आंतरिक निर्णय है।

बिहार के जमुई, गयाजी और मुंगेर की परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सम्राट चौधरी

नई दिल्ली,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में उपलब्ध बंजर वन भूमि का औद्योगिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों की छह प्रमुख परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपयोजन से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें 45.9 हेक्टेयर वन भूमि पर गयाजी चिड़ियाघर के निर्माण के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, जमुई जिले में प्रस्तावित सौर ऊर्जा और इस्पात उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 9,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इसमें से 4,340 एकड़ वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति मांगी गई है।

गयाजी जिले के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इसके लिए कुल 1,600 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसमें 1,308.72 एकड़ वन भूमि शामिल है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के अंतर्गत 5.8 किलोमीटर लंबे मदनपुर-पनियहवा पथ की मरम्मत और उसे प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं, मुंगेर जिले के तारापुर



अनुमंडल के संग्रामपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कुल 114 एकड़ भूमि में से 84 एकड़ जंगल-झाड़ भूमि के अपयोजन की स्वीकृति मांगी गई है। मुंगेर जिले के भीमबांध क्षेत्र में ईको टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए प्रतिपूरक वनीकरण से जुड़े वैधानिक प्रावधानों तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके क्रियान्वयन से बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। इससे पर्यटन और आधारभूत संरचना को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। सभी परियोजनाओं को निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, प्रतिपूरक वनीकरण और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रस्तावों का शीघ्र परीक्षण करने और नियमानुसार आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहयोग का अनुरोध किया।

अक्टूबर में किशनगंज पुलिस का अपराधियों पर प्रहार, 230 गिरफ्तार, 2.30 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त

किशनगंज। जिले में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किशनगंज पुलिस ने अक्टूबर माह में अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर एक से 31 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान में अपराधियों, नशा तस्करों, शराब कारोबारियों, बालू माफियाओं और मवेशी तस्करों पर शिकंजा कसा गया।

एक महीने तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में कुल 230 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अभियान के दौरान 995.5 ग्राम ब्राउन शुगर, स्मैक एवं हेरोइन बरामद की गई, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये आंका गया है। इसके अलावा 294 ग्राम एमडीएमए और 3.888 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। मादक पदार्थों की इतनी बड़ी बरामदगी से जिले में सक्रिय नशा तस्करी के नेटवर्क पर पुलिस की सख्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं, मद्यनिषेध अभियान के तहत पुलिस ने 1144.795 लीटर विदेशी शराब और 234.75 लीटर देसी शराब बरामद की। इसके साथ ही 920 लीटर जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में 37 मवेशी, 22 मोबाइल फोन, 16 ट्रक एवं ट्रैक्टर तथा 12 मोटरसाइकिल और साइकिलें जब्त की गईं। इधर, यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 14 लाख 53 हजार 21 रुपये का जुर्माना वसूल किया। पुलिस ने गृहभेदन, बाइक चोरी और फर्जी कंपनी संचालित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 60 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और शिथिलता बरतने के आरोप में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि चार कर्मियों को विभागीय स्तर पर दंडित किया गया।पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने आम लोगों से अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ सहयोग की अपील की है। मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी की सूचना एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 9031816150, साइबर ठगी की शिकायत 1930 और आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए 112 पर संपर्क करने की अपील की गई है।

सब्सिडी छोड़ने की अपील से पहले बिजली विभाग के भ्रष्टाचार का हिसाब दे सरकार: अनुपम

सुपौल। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि सरकार जनता से त्याग की अपेक्षा करने के बजाय पहले सरकारी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जवाबदेही सुनिश्चित करे। अनुपम ने कहा कि मुख्यमंत्री का तर्क है कि बिहार सरकार बिजली सब्सिडी पर प्रतिवर्ष करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। संपन्न लोग यदि 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें तो बची राशि विकास कार्यों में लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल है कि सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ के लिए केवल नागरिकों से त्याग की अपेक्षा क्यों की जा रही है? सरकारी धन का सदुपयोग और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुपम ने मुख्यमंत्री से पांच बिंदुओं पर जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि क्या मुफ्त बिजली देना सरकार की नीतिगत जिम्मेदारी नहीं है, जिसे नागरिकों पर एहसान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? बिजली सब्सिडी पर खर्च हो रहे 23 हजार करोड़ रुपये का विस्तृत हिसाब, लाभार्थियों की संख्या और उपभोक्ता श्रेणियों के अनुसार खर्च का ब्योरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि संपन्न लोगों के सब्सिडी छोड़ने से होने वाली बचत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और ग्रामीण विकास पर किस अनुपात में तथा किस समयसीमा के भीतर खर्च की जाएगी? बिजली विभाग में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी ठेकों की अनियमितताओं की जांच पूरी कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा उन्होंने सरकार से शिक्षा, खेल और ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक बजट, कार्ययोजना और समयबद्ध लक्ष्य सार्वजनिक करने की मांग की। अनुपम ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय सरकार की नीतिगत जिम्मेदारी है और उसके वित्तीय प्रबंधन की जवाबदेही भी सरकार की ही है।

आईपीएस कुंदन कृष्णन की संपत्ति को लेकर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल, जांच की मांग

पटना,एजेंसी। बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर घोषित संपत्ति के अलावा भी कई जमीनें और निवेश हैं, जिनका विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। सांसद ने दूसरे लोगों के नाम पर जमीन खरीदने और संभावित बेनामी संपत्ति का मामला भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

सुधाकर सिंह ने कहा कि कुंदन कृष्णन को अपने माता-पिता से करीब 38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति विरासत में मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरासत में मिली संपत्ति को लेकर वह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका सवाल अधिकारी और उनकी पत्नी डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर अर्जित संपत्तियों को लेकर है। सांसद के मुताबिक, दोनों की ओर से घोषित संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 87 करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि इसके अतिरिक्त भी कई जमीनें और निवेश हैं, जिनका उल्लेख संपत्ति के विवरण में नहीं किया गया है। सांसद ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल की है और कुछ जमीनों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी कराया है। उन्होंने कैमूर जिले में करीब 16 एकड़ 88 डिसमिल कृषि भूमि की खरीद का मामला उठाया। उनके अनुसार, इस जमीन का बाजार मूल्य करीब दो करोड़ रुपये है, जबकि दस्तावेजों



में इसकी कीमत लगभग 17.50 लाख रुपये दर्ज है। उन्होंने जमीन की खरीद में नकद भुगतान किए जाने का भी आरोप लगाया। सुधाकर सिंह ने नालंदा जिले में कुंदन कृष्णन के पैतृक गांव के पास दिनेश राम नामक व्यक्ति से जमीन खरीदे जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस जमीन का उल्लेख संपत्ति की घोषणा में नहीं किया गया है। इसके अलावा, पटना के मालसलामी इलाके के सिमरी-मुरारपुर में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 10 कट्ठा जमीन होने की बात कही। सांसद ने इसका बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान जताया। वहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में कुंदन कृष्णन के नाम पर साढ़े तीन से साढ़े चार कट्ठा जमीन होने का भी दावा किया। सांसद ने मालसलामी के अलग-अलग प्लॉट का विवरण देते हुए कहा कि एक प्लॉट में डॉ. मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 40 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 60 कट्ठा जमीन है। दूसरे प्लॉट में मल्लिका सिंह के नाम पर करीब 34 कट्ठा और बिट्टू सिंह के नाम पर करीब 70 कट्ठा जमीन होने का दावा किया गया। सुधाकर सिंह ने इन संपत्तियों की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये होने का अनुमान जताया। हालांकि, जमीनों के वास्तविक रकबे, बाजार मूल्य और स्वामित्व की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सुधाकर सिंह ने शेयर बाजार में निवेश से जुड़े दस्तावेजों का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के नाम पर एक्सिस बैंक, बजाज हिंदुस्तान, भारती टेलीवेंचर्स, सिप्ला, फोर्टिस हेल्थकेयर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एनएमडीसी सहित कई कंपनियों के शेयर रहे हैं।

दीपावली एवं छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

अररिया। आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों के अस्थायी भंडारण एवं विक्रय को लेकर डीएम विनोद दूहन द्वारा आदेश जारी कर संबंधित पदाधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने निर्देश दिया गया है। विस्फोटक नियमावली- 2008 के नियम 84 एवं एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट रूल्स, 2019 के प्रावधानों के तहत जिले में अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत करने तथा बिक्री के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के लिए निर्धारित स्थल अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होना चाहिए तथा वहां अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पटाखों के धारण स्थल एवं विक्रय स्थल के बीच कम से कम 3 मीटर तथा संरक्षित कार्य से कम से कम 50 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। विक्रय स्थल और संरक्षित स्थल आमने-सामने नहीं होने चाहिए।

पटाखा बिक्री स्थलों पर तेल से जलने वाले लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी के उपयोग पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध रहेगा। बिजली की रोशनी का उपयोग करने पर वायरिंग भवन की दीवार या छत में फिक्स होनी चाहिए। झूलते हुए बिजली के तार का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान का स्विच अलग-अलग दीवार पर फिक्स होगा तथा मास्टर स्विच कतारबद्ध रहेगा। पटाखों का



प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं बनाया जाएगा। एक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों की ही अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पटाखा दुकानों के प्रत्येक क्लस्टर में फर्स्ट एड एम्बुलेंस एवं कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सभी क्लस्टरों में विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री से संबंधित चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करना होगा। अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शीर्ष में पांच सौ रुपये का चालान जमा करना होगा। चालान जमा करने के बाद ही नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में पर्यावरण संरक्षण और न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, आतिशबाजी के लिए निर्धारित समय सीमा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगी। इस समय सीमा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को निर्धारित शर्तों और न्यायालय के निर्देशों के अधीन अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भागलपुर के रेशम को मिलेगा बड़ा बाजार, जीरो माइल में खरीदारों और उत्पादकों का हुआ महाजुटान

भागलपुर। अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध भागलपुर के रेशमी वस्त्रों को अब बड़े बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्थानीय रेशम उत्पादकों को बड़े खरीदारों से जोड़ने, उनके उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से जीरो माइल स्थित रेशम भवन में मंगलवार को एक भव्य बॉयर्स-सेलर्स मीट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जीविका एवं वूमेन वर्ल्ड बैंकिंग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री रवि राकेश ने किया। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनिर्मल गरेन और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी, सिल्क उद्यमी, उत्पादक समूहों की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में खरीदार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त राकेश ने कहा कि तसर सिल्क भागलपुर की विशिष्ट पहचान और गौरव रहा है। यहां के रेशमी वस्त्रों की गुणवत्ता एवं पारंपरिक बुनाई कला की दुनिया दीवानी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय सिल्क उत्पादकों और बड़े खरीदारों के बीच सीधा संपर्क एवं बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए नए बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इस बॉयर्स-सेलर्स मीट में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करने वाले महिला समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों ने अपने बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य और हैंडलूम सिल्क के उत्पादन व व्यवसाय से जुड़ीं बीवी शबनम, प्रति कुमारी, अमृता कुमारी, फरजान और जूली कुमारी सहित भागलपुर की कई महिला उद्यमियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इसके साथ ही पड़ोसी जिले बांका से आए कुछ सिल्क उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया और अपने उत्पादों व व्यावसायिक अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान देश के कोने-कोने से आए खरीदारों और स्थानीय उत्पादकों के बीच उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक डिजाइन, सही कीमत, बाजार की मांग, आपूर्ति श्रृंखला तथा भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे मुख्यधारा के बाजार से जोड़ना, उचित मूल्य दिलाना और उनके व्यवसाय को एक व्यापक पहचान प्रदान करना है। जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह बॉयर्स-सेलर्स मीट भागलपुर के पारंपरिक रेशम उद्योग को नई व्यावसायिक ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ महिला उद्यमियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

एक नजर

वेस्टइंडीज महिला टीम के कोच डिएट्ज ने छोड़ा पद, कोली को अंतरिम जिम्मेदारी



किंग्सटन,एजेंसी। वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच शेन डिएट्ज ने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। डिएट्ज का अनुबंध अक्टूबर के अंत में समाप्त हो गया था। उनके स्थान पर वेस्टइंडीज पुरुष टेस्ट टीम के पूर्व कोच आंद्रे कोली को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोली आगामी पाकिस्तान दौरे के दौरान वेस्टइंडीज महिला टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। सीडब्ल्यूआई के क्रिकेट निदेशक माइल्स बासकॉम्ब ने कहा कि डिएट्ज के मार्गदर्शन में टीम ने लगातार दो महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने इस प्रदर्शन को टीम के लिए एक नया मानक बताया। डिएट्ज के कार्यकाल में वेस्टइंडीज की महिला टीम 2024 और 2026 के टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि, 2024 में उसे न्यूजीलैंड और इस साल ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बासकॉम्ब ने बताया कि डिएट्ज ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बोर्ड को जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने टीम के हित में नेतृत्व परिवर्तन को उचित समय पर करने और जिम्मेदारी का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी : बुधवार को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा गत चैंपियन भारत



मोहाली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बुधवार को हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। गत चैंपियन भारत की नजरें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर खिताब बचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने पर होंगी। टूर्नामेंट का लीग चरण जालंधर में खेला गया था, जबकि अब मुकाबले मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होंगे। हॉकी इंडिया के अनुसार भारतीय टीम ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी पांच मुकाबले जीते और बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसमें सोमवार को जालंधर में आखिरी लीग मुकाबले में दक्षिण कोरिया पर 8-0 की जीत भी शामिल है। अब दोनों टीमें तीन दिन में दूसरी बार आमने-सामने होंगी। हालांकि, सेमीफाइनल का मुकाबला दोनों टीमों के लिए नई चुनौती होगा। भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कोरिया के खिलाफ जीत के बाद कहा था कि नॉकआउट मुकाबले का दबाव अलग होगा और टीम को अच्छी शुरुआत करनी होगी। लीग चरण में भारतीय टीम की सफलता में उसके सभी फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया है। सुखजीत सिंह और दिलप्रीत सिंह ने अच्छी फार्म दिखाई है। दोनों ने टूर्नामेंट में अब तक चार-चार गोल किए हैं। वहीं, अभिषेक के नाम तीन गोल हैं। हालांकि, चोट के कारण वह दक्षिण कोरिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह नौ गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। टीम के एक अन्य ड्रैग फ्लिकर जुगराज सिंह ने भी तीन गोल किए हैं। भारत 15 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। टीम ने लीग चरण में कुल 34 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ केवल पांच गोल हुए। अब भारतीय टीम इसी प्रदर्शन को सेमीफाइनल में भी दोहराते हुए छठी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतना चाहेगी। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने 2011, 2016, 2018 (पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता), 2023 और 2024 में ट्रॉफी जीती है।

श्याम लाल कॉलेज का अंतर कॉलेज हॉकी खिताब पर कब्जा बरकरार



नई दिल्ली। दिल्ली के श्याम लाल कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के खिताब पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। श्याम लाल कॉलेज ने प्रतियोगिता में अपराजित रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। सुपर लीग के अंतिम लीग मैच में श्याम लाल कॉलेज ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को 9-0 से हराकर पूरे अंक अर्जित किए। श्याम लाल कॉलेज की तरफ से प्रत्यूष सिंह जग्गी ने तीन गोल, नंदकिशोर ने दो गोल और मोहम्मद आमिर, भूपेंद्र, हर्ष यादव और कप्तान के. रोहित ने एक- एक गोल किया। गोल औसत के आधार पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को दूसरा स्थान मिला और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को तीसरा स्थान मिला। मेजबान श्याम लाल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. रबि नारायण कर की घोषणा के अनुसार पहले तीन स्थानों पर रही टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए गए। आखिरी दिन सुपर लीग के मैच में श्रीराम कॉलेज ने हंसराज कॉलेज को 4-1 से हराया। यह पहला मौका था, जब बारिश की वजह से श्याम लाल कॉलेज का मैदान गीला होने के कारण अंतिम दिन के मैच पूर्वी दिल्ली के झिलमिल एस्ट्रो टर्फ मैदान पर खेले गए, जिससे खिलाड़ियों को अलग और अच्छा अनुभव मिला।

दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त, जायसवाल और राठौड़ ने जड़े शतक



क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड)। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेला गया दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 155 रन बनाए, जबकि यश राठौड़ ने नाबाद 100 रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के इस प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए और मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रही। जायसवाल और राठौड़ ने तीसरे विकेट के लिए 247 रन की अटूट साझेदारी की। एक समय इंडिया ए ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी संभालते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पहला मुकाबला भी ड्रॉ रहा था। तीसरा और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट मैच 7 नवंबर से खेला जाएगा। चौथे दिन बारिश और बूंदाबांदी के कारण खेल देर से शुरू हुआ। खेल शुरू होते ही न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों ने इंडिया ए को दो झटके दिए। साई सुदर्शन 11 रन और देवदत्त पडिक्कल बिना खाता खोले आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद जायसवाल ने आक्रामक अंदाज अपनाया और न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया। उनका साथ देने आए राठौड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी की।

जायसवाल ने आक्रमक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 119 गेंदों में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। दूसरी ओर, यश राठौड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा किया। जायसवाल ने 162 गेंदों में नाबाद 155 रन की पारी में 15 चौके और पांच छक्के लगाए, जबकि राठौड़ ने अपनी नाबाद 100 रन की पारी में नौ चौके लगाए। इससे पहले न्यूजीलैंड ए ने मैथ्यू बॉयल के 110 और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के 93 रन की बदौलत पहली पारी में 424 रन बनाए थे। इनके अलावा पहली पारी में न्यूजीलैंड के फ्रेजर शीट ने 40 रन, क्रिस्टियन क्लार्क ने 41 रन, मिचेल हे 31 रन, जेडेन लेनॉक्स नाबाद 32 रन और जैरोड मैके ने 33 रन की पारी खेली। वहीं, इंडिया ए ने विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के 105 रन की मदद से पहली पारी में 346 रन बनाए थे। जुरेल के अलावा पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल 80 और आकाश दीप ने 68 रन का योगदान दिया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम है। इस सीरीज से पहले दोनों देशों की ए टीमों के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है।

आईसीसी वनडे रैंकिंग : वैष्णवी शर्मा ने लगाई 53 स्थान की छलांग, 94वें नंबर पर पहुंची



नई दिल्ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ियों को आईसीसी महिला वनडे प्लेयर रैंकिंग में फायदा हुआ है। गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग 20 वर्षीय भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने लगाई है। वह 53 स्थान ऊपर चढ़कर 94वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वैष्णवी ने सीरीज के दूसरे वनडे में चार विकेट हासिल किए थे। इसके बाद आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट चटकाए थे। वनडे करियर का अपना केवल तीसरा मैच खेल रहीं वैष्णवी ने 39 रन देकर पांच विकेट हासिल किए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज सयाली सतघारे को भी फायदा हुआ है। सयाली ने आखिरी वनडे में छह ओवर में 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे। इसके परिणामस्वरूप वह 18 स्थान की छलांग लगाकर 85वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, इस मुकाबले में दो विकेट लेने वाली क्रांति गौड़ भी एक स्थान ऊपर चढ़कर 24वें नंबर पर पहुंच गई हैं। जिम्बाब्वे की नोमवेलो सिबांडा को भी गेंदबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है। आखिरी वनडे में एक विकेट हासिल करने के बाद वह दो स्थान ऊपर चढ़कर 60वें नंबर पर पहुंच गई हैं।

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने सुधार किया है। सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक लगाने के बाद वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं। सीरीज के आखिरी वनडे में आक्रामक अंदाज में 51 रनों की पारी खेलने वाली शेफाली वर्मा को आठ स्थान का फायदा हुआ है। वह अब संयुक्त रूप से 65वें स्थान पर पहुंच गई हैं। जिम्बाब्वे की खिलाड़ियों ने भी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया है। आखिरी मुकाबले में 37 रन बनाने वाली सलामी बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा तीन स्थान ऊपर चढ़कर 36वें नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि टीम की कप्तान जोसेफिन नकोमो को दो स्थान का फायदा हुआ है और वह 49वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

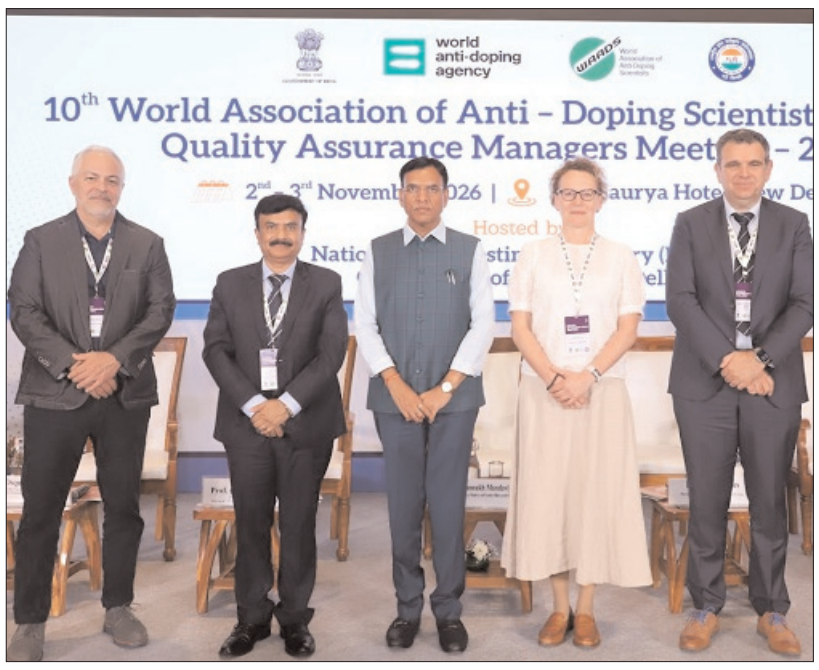
महिला विश्व कप जीत के एक साल पूरे, प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा ने साझा किए यादगार पल

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने का दशकों लंबा इंतजार आखिरकार 2 नवंबर 2025 को खत्म हुआ था। इस दिन भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इस ऐतिहासिक जीत के एक साल पूरे होने पर जियोस्टार के विशेष कार्यक्रम 'सेलिब्रेटिंग द चैंपियंस' में भारतीय टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा ने विश्व कप से जुड़े यादगार पलों को साझा किया। प्रतिका रावल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल में उसी तारीख पर शतक लगाने की खास कहानी सुनाई, जिस तारीख को उन्होंने 2025 विश्व कप में भी शतक जड़ा था। साथ ही प्रतिका ने बांग्लादेश के खिलाफ लगी चोट और विश्व कप से बाहर होने के मुश्किल दौर को भी याद किया। वहीं, शेफाली वर्मा ने टूर्नामेंट के बीच अचानक टीम में शामिल किए जाने का अनुभव साझा किया।

भारतीय बल्लेबाज प्रतिका रावल ने बीते 23 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शतक लगाने के पीछे की दिलचस्प कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरने वाली थीं, तब टीवी पर 2025 महिला विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुकाबले की झलकियां दिखाई जा रही थीं। प्रतिका के मुताबिक, टीवी पर एक तारीख का जिक्र देखकर उन्हें याद आया कि इसी दिन उन्होंने विश्व कप में भी शतक लगाया था।

प्रतिका ने बताया कि क्मैं स्मृति दीदी और अमोल सर (कोच) के साथ इस बारे में बात कर रही थी। हमने उसी पल इस उपलब्धि को दोहराने का फैसला किया। इसके बाद मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। उसी तारीख पर दोबारा शतक बनाना मेरे लिए बेहद खास अनुभव था।' प्रतिका रावल ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान लगी चोट और इसके कारण विश्व कप से बाहर होने के मुश्किल समय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि क्जब मैं बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान गिरी, तभी मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह समझती हूं और चोट का असर सामान्य नहीं लग रहा था। एक्स-रे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका विश्व कप अभियान समाप्त हो गया।' उन्होंने कहा कि क्विश्व कप के बीच चोटिल होना बेहद दुखद था। हालांकि, सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम को खेलते देखना उनके लिए शानदार अनुभव रहा।

डोपिंग पर लगाम के लिए शोध और जागरूकता पर जोर, एनडीटीएल की नई नीति शुरू



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत खेलों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए डोपिंग के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा है। खिलाड़ियों की जीत प्रतिभा, अनुशासन और मेहनत के आधार पर हो, इसके लिए जांच व्यवस्था को मजबूत करने के साथ जागरूकता और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डॉ मांडविया ने मंगलवार को नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी वैज्ञानिक संघ (डब्ल्यूएएडीएस) की गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधकों की 10वीं बैठक में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) की बाह्य अनुसंधान अनुदान नीति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एनडीटीएल के न्यूजलेटर का भी लोकार्पण किया। खेल मंत्री ने कहा कि नई अनुसंधान अनुदान नीति का उद्देश्य डोपिंग का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए उन्नत तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे डोपिंग रोधी अभियान को वैज्ञानिक मजबूती मिलेगी और जांच की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों और सप्लीमेंट के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। प्रशिक्षकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को भी डोपिंग रोधी नियमों के प्रति जागरूक होना चाहिए। मांडविया ने कहा कि भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य भी रखता है। ऐसे में स्वच्छ खेल, प्रभावी डोपिंग जांच, खिलाड़ी शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग देश की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से देश का खेल तंत्र मजबूत हुआ है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अधिक अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण आधार के रूप में पहचान मिली है। बैठक में खेल सचिव हरि रंजन राव, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के वरिष्ठ अधिकारी डॉ ओस्क्वेल बारोसो, डब्ल्यूएएडीएस की अध्यक्ष डॉ डोरोटा क्वियात्कोव्स्का और एनडीटीएल के निदेशक प्रो. पीएल साहू सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद रहे।

रक्षा खडसे ने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मंगलवार को नई दिल्ली में चल रही 47वीं वर्ल्ड आर्मरेसलिंग और 28वीं विश्व पैरा आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। भारत में पहली बार आयोजित हो रही यह चैंपियनशिप 6 नवंबर तक चलेगी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर से हुई थी। इसमें 60 से अधिक देशों के 1,700 से ज्यादा एथलीट, अधिकारी और समर्थक शामिल हैं।

इस चैंपियनशिप का आयोजन 'पीपल्स आर्मरेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया' (पीएएफआई) द्वारा किया जा रहा है। इसका नेतृत्व पीएएफआई की अध्यक्ष और एशियन आर्मरेसलिंग फेडरेशन की उपाध्यक्ष प्रीति झंगियानी तथा 'प्रो पंजा लीग' के सह-संस्थापक परवीन डबास कर रहे हैं। यह आयोजन 'वर्ल्ड आर्मरेसलिंग फेडरेशन की संबद्धता और मार्गदर्शन में हो रहा है। आयोजन के दौरान मंत्री खडसे ने मुकाबले देखे, खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की और भारत के आर्म-रेसलरों तथा पैरा आर्म-रेसलरों सहित सभी भाग लेने वाले देशों के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि क्हमारे लिए यह बहुत बड़ा अवसर है कि भारत 2026 में 47वीं वर्ल्ड आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप और 28वीं पैरा वर्ल्ड आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। यहां मौजूद सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं भारत में भी इस आर्मरेसलिंग प्रतियोगिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हूं। इस तरह, हम सब मिलकर अपने देश के लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर सकते हैं। वर्ल्ड आर्मरेसलिंग और पैरा-आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 58 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 19 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इन पदकों में पैरा श्रेणियों में 26, सब-जूनियर, जूनियर और यूथ श्रेणियों में 20 तथा मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स श्रेणियों में 12 पदक शामिल हैं।

मनु भाकर 2026-2030 के लिए आईएसएसएफ एथलीट्स कमेटी का चुनाव लड़ेंगी

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 2026-2030 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) एथलीट्स कमेटी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। उन्हें पिस्टल वर्ग से उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। इस वर्ग में दो पदों के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अनुसार मनु भाकर ने चुनाव के लिए खिलाड़ियों पर केंद्रित अपना विजन भी सामने रखा है। उनका उद्देश्य दुनियाभर के निशानेबाजों के लिए खेल को अधिक सुरक्षित, सहयोगात्मक और बेहतर बनाना है। मनु का मानना है कि अपने खेल के भविष्य को तय करने वाले फैसलों में खिलाड़ियों की आवाज अधिक मजबूत होनी चाहिए। उनका विजन एक खिलाड़ी के सफर के अहम पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें प्रतियोगिता के प्रारूप और आर्थिक अवसरों से लेकर, मानसिक स्वास्थ्य, करियर की सुरक्षा और खेल के प्रशासनिक ढांचे में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। मनु भाकर के एजेंडे में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के भविष्य को सुरक्षित रखना प्रमुख प्राथमिकता है। वह चाहती हैं कि इस स्पर्धा को ओलंपिक कार्यक्रम में बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाएं। उनका लक्ष्य ओलंपिक चक्रों के दौरान तकनीकी नियमों में अधिक स्थिरता की वकालत करना भी है, ताकि एथलीट बेहतर निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर सकें। इसके अलावा वह आईएसएसएफ विश्व कप में बेहतर इनामी राशि के लिए जोर देना चाहती हैं। साथ ही वह ऐसे टीवी-अनुकूल प्रतियोगिता प्रारूपों के जरिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाना चाहती हैं, जो प्रसारकों और प्रायोजकों को आकर्षित कर सकें और खिलाड़ियों के लिए अधिक मूल्य पैदा कर सकें। मनु भाकर शूटिंग खेल को दुनियाभर में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करने की भी पक्षधर हैं। उनके विजन में खिलाड़ियों की समस्याओं को सीधे आईएसएसएफ नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करना भी शामिल है। वह खिलाड़ियों की शिकायतों के समाधान के लिए सुरक्षित और गोपनीय व्यवस्था बनाने की वकालत करेंगी, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटारा हो सके। मनु व्यावहारिक वित्तीय सुरक्षा और करियर-बदलाव के ऐसे रास्तों की वकालत करना चाहती हैं, जो एथलीटों को खेल से संन्यास लेने के बाद एक स्थिर जीवन बनाने में मदद कर सकें। अपनी उम्मीदवारी पर मनु भाकर ने कहा कि आईएसएसएफ एथलीट्स कमेटी के लिए नामित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को केवल खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इसके भविष्य को तय करने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा लक्ष्य प्रतियोगिता के नियमों में अधिक स्थिरता, बेहतर वित्तीय और व्यावसायिक अवसर, खिलाड़ियों के कल्याण के लिए मजबूत व्यवस्था और अपनी समस्याएं रखने के लिए अधिक सुलभ मंच उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है।

एक नजर

युद्धविराम प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब से संतुष्ट नहीं ईरान, होर्मुज खोलने से इनकार



तेहरान,एजेंसी। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने कहा है कि युद्धविराम के प्रस्ताव पर अमेरिका का जवाब संतोषजनक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की सात शर्तों को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से स्वीकार किए जाने तक होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए नहीं खोला जाएगा। रजाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अमेरिका ने ईरान के अधिकारों और मांगों पर जो जवाब दिया है, वह भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान की सभी सात शर्तों पर स्पष्ट रुख अपनाने के साथ उन्हें लागू भी करना होगा। इसके बाद ही होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर विचार किया जाएगा। ईरान की प्रमुख मांगों में युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना, गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइली सैन्य कार्रवाई रोकना, ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाना और पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी शामिल है। इसके अलावा तेहरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने, युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही के लिए ईरान की ओर से तय की जाने वाली नई व्यवस्था को मान्यता देने की मांग भी रखी है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम समुद्री मार्ग है। ऐसे में इसे खोलने या बंद रखने को लेकर ईरान का रुख क्षेत्रीय तनाव के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी असर डाल सकता है।

ट्रंप का दावा, साल के अंत तक इजराइल को सैन्य मदद देना बंद करेगा अमेरिका

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका इस साल के अंत तक इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता पूरी तरह बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस संबंध में समझौता हो चुका है और इजराइल भी इस फैसले के लिए तैयार है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका इजराइल को हर साल करीब चार अरब डॉलर की सहायता देता है, लेकिन अब इसे रोकने पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल आर्थिक और सैन्य रूप से सफल देश बन चुका है और उसे अब इस मदद की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका इजराइल की सहायता करता रहेगा और उसे अपना करीबी सहयोगी मानता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य सहायता को लेकर हुआ 10 साल का समझौता 2028 के अंत तक प्रभावी है। इसके तहत इजराइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी जाती है। दूसरी ओर, नेतन्याहू पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि इजराइल भविष्य में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता समाप्त करना चाहता है। हालांकि, उनकी योजना इसे अचानक बंद करने के बजाय अगले दशक में धीरे-धीरे खत्म करने की रही है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल और पूर्व मंत्री समेत 97 लोगों के खिलाफ मुकदमा



काठमांडू। नेपाल के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और पूर्व मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ. मिनेन्द्र रिजाल समेत 97 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है। आयोग ने मंगलवार को इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। यह मुकदमा सुनसरी जिले के इटहरी स्थित रिजाल कैनिंग कंपनी (रिजाल टासी इंडस्ट्रीज) की निर्धारित भूमि सीमा से अधिक जमीन बेचने के आरोप में दर्ज किया गया है। आयोग के अनुसार, कंपनी के पास निर्धारित सीमा से अधिक जमीन थी। आरोप है कि इस जमीन को मंत्रिपरिषद से निर्णय कराकर जमीन की अदला-बदली के नाम पर बेचा गया। आयोग ने आरोप लगाया है कि माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री रहते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में ही निर्धारित भूमि सीमा से अधिक जमीन बेचने की अनुमति दी गई थी। इसी आरोप के आधार पर आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है।

नेपाल के नए भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला काठमांडू पहुंचे, संभालेंगे कार्यभार

काठमांडू। नेपाल के लिए नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला अपना कार्यभार संभालने के लिए सोमवार को काठमांडू पहुंचे। दोपहर करीब दो बजे एयर इंडिया के विमान से त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे दलेला का भारतीय दूतावास के उप प्रमुख डॉ. राकेश पांडेय और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वागत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही दलेला को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया था। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के पद पर कार्यरत थे। दलेला इससे पहले भूटान में भी भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नेपाल और भूटान से संबंधित मामलों को देखने वाले नॉर्थ डेस्क के प्रभारी भी रह चुके हैं। नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। दलेला के नेपाल पहुंचने के बाद अब उनके जल्द ही औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने की उम्मीद है।



नेतन्याहू का आतंकवाद विरोधी दलों से लिकुड के साथ आने का आह्वान

यरुशलम (इजराइल),एजेंसी। इजराइली संसद (नेसेट) के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी लिकुड के नेता और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद विरोधी दलों से राष्ट्रीय सरकार बनाने सहयोग देने का आह्वान किया है। नेतन्याहू ने सोमवार रात सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'इजराइली जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती जो राअम और जॉइंट लिस्ट जैसे दलों पर निर्भर हो। यह दल आतंकवाद का समर्थन करते हैं। यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को नकारते हैं।

द यरुशलम पोस्ट और द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, 'पहले दिन से ही हमने एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है।' नेतान्याहू ने कहा, 'यहूदी जनता के स्पष्ट बहुमत ने लिकुड को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है और मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर अगली सरकार का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। हम अपने सहयोगियों और किसी भी अन्य ऐसी पार्टी के साथ मिलकर एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते हैं। आतंकवाद विरोधी दल हमारे साथ आएं। नेतान्याहू ने कहा, 'मैं इस विषय पर खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार हूं।' पिछले हफ्ते हुए चुनाव के बाद यह पहली बार है जब उन्होंने राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कही है। चुनाव नतीजों में लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीतीं हैं। लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू के गुट के पास कुल 53 सीटें हैं। 120 सदस्यीय नेसेट के चुनाव में यशार पार्टी ने 21 सीटें जीतीं और इसके चेयरमैन गादी आइसेनकोट के गुट के पास कुल 48 सीटें



आई हैं। वहीं, अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीतीं। इनमें राअम पार्टी प्रमुख है। यह मुख्य रूप से इजराइल में रहने वाले अरब नागरिकों और बेडौइन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अरब-इस्लामी राजनीतिक पार्टी है।

उधर, बुधवार को राष्ट्रपति हर्जोग के सामने चुनाव के आधिकारिक नतीजे पेश किए जाएंगे। लिकुड पार्टी ने कहा कि इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इस मांग को ठुकरा दिया है। लिकुड पार्टी का दावा है कि अरब पार्टियों ने वोट 'चुरा' लिए हैं। इजराइल के उच्चतम न्यायालय के जज नोम सोहलबर्ग ने भी इस मांग को खारिज कर दिया। इस समय 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में विदेशी दखलंदाजी के संदेह की जांच चल रही है। सोहलबर्ग की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने स्पष्ट किया कि अगर ये आरोप साबित भी हो जाएं तो भी इतने गंभीर नहीं हैं कि चुनाव के नतीजों को बदल सकें। समिति ने कहा कि चुनाव 'सही तरीके से कराए गए।' ये दावे इस आरोप के इर्द-गिर्द हैं कि कतर या अन्य विदेशी ताकतों ने अरब मतदाताओं की संख्या बढ़ाने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुप्त रूप से फंडिंग की। इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और उम्मीद है कि शिन बेट और मोसाद जल्द ही अपनी जांच पूरी कर लेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति बुधवार को चुनाव नतीजों को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान करेगी। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लिकुड पार्टी इसका विरोध करने पर विचार कर रही है।

दीपावली से पहले काठमांडू में प्लास्टिक के फूल और माला बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध



काठमांडू। नजदीक आ रहे दीपावली पर्व को देखते हुए काठमांडू महानगरपालिका ने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक से बने फूलों, फूलों की मालाओं और सजावट के विभिन्न सामानों की बिक्री एवं वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। महानगरपालिका ने सभी व्यवसायियों, व्यापारियों और आम लोगों से फूलों और मालाओं के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की अपील की है। काठमांडू महानगरपालिका के नगर कार्यपालिका कार्यालय के अंतर्गत आने वाले महानगर पुलिस बल ने एक सूचना जारी कर चेतावनी दी है कि प्रतिबंध की अवहेलना कर यदि कोई प्लास्टिक से बने या निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले फूल, मालाएं और सजावट के सामान बेचते हुए पाया गया, तो उन सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया जाएगा। महानगर पुलिस बल ने नेपाली किसानों के उत्पादित फूल-मालाओं को उचित बाजार उपलब्ध कराने तथा आम लोगों को आसानी से खरीदारी की सुविधा देने के उद्देश्य से संबंधित निकायों के समन्वय में बिक्री के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित किए हैं।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान कुछ देर बाद शुरू होगा

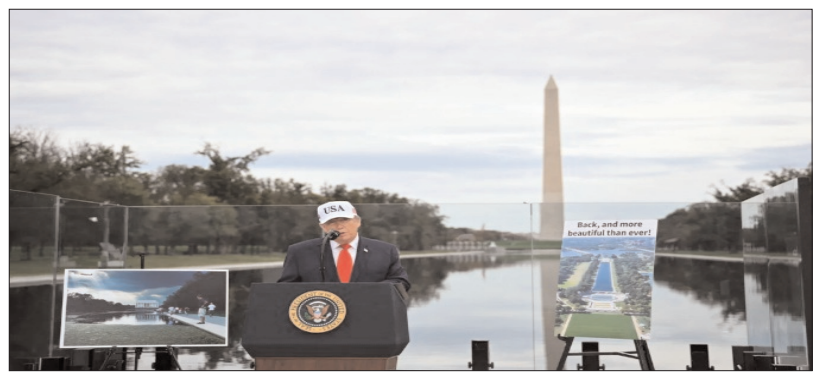
वाशिंगटन। अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान शुरू होने जा रहा है। भारतीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे मतदान शुरू होगा। अमेरिकी समयानुसार मतदान केंद्र अलग-अलग राज्यों में सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे के बीच खुलेंगे। भारतीय समयानुसार मतदान चार नवंबर को सुबह 5:30 बजे समाप्त होगा। इसके ठीक बाद शुरुआती नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। वाशिंगटन के कैपिटल हिल में सवेरा होने वाला है। मध्यावधि चुनाव यह तय करेंगे कि कांग्रेस पर किसका राजनीतिक नियंत्रण होगा। अमेरिकी नागरिक 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' की सभी 435 सीट, सीनेट की 35 सीट और 36 गवर्नर के पदों के लिए मतदान करेंगे। इससे यह तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो सालों में कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बना रहता है या डेमोक्रेटिक पार्टी एक या दोनों सदनों में फिर से जीत हासिल करती है। सीएनएन के 'पोल ऑफ पोल्स' के अनुसार जेनेरिक कांग्रेसनल बैलेट में डेमोक्रेट्स को 9 अंकों की बढ़त हासिल है। साथ ही चुनावी विश्लेषकों ने भी कई कड़े मुकाबले वाली सीटों को लगातार डेमोक्रेट्स के पक्ष में जाते हुए दिखाया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स-सिएना के पोल के मुताबिक सीनेट की पांच अहम सीटों पर भी डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी लगातार गैर नागरिकों पर व्यापक मतदान और चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसे चुनाव अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की धमकी दी है जो मतदान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं या गैर-नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया में विवादित मतपत्रों की गिनती को प्रतिबंधित करने और अलास्का में परिणामों के प्रमाणीकरण को रोकने के लिए मुकदमे दायर किए हैं। इस बीच कई राज्यों ने किसी भी टकराव से पहले संभावित कानूनी चुनौतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। कुछ ने पहले से ही बाहरी वकीलों को नियुक्त कर लिया है। वे संघीय हस्तक्षेप की स्थिति में अदालत जाने और तत्काल राहत या कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हैं। इस बार कम से कम 10 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल, सीनेट में दो निर्दलीय सदस्य हैं- वरमोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स और मेन के सीनेटर एंगस किंग।

अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर किया हमला

वाशिंगटन (अमेरिका)/तेहरान (ईरान)। अमेरिका ने कतर के अधिकारियों के जरिए ईरान के साथ चल रही समझौते की बातचीत के दौरान केशम द्वीप पर हमला किया है। तीन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को ईरान के केशम द्वीप पर सीमित हमले किए। उन्होंने इसे बचाव की कार्रवाई बताया और कहा इसका मकसद इलाके में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों की सुरक्षा करना है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इन तीन अधिकारियों से एक ने बताया कि यह हमला ईरान के एक अमेरिकी विमान पर गोलीबारी करने के जवाब में किया गया। यह कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं है। दूसरे अधिकारी ने कहा, 'यह कदम बचाव के लिए उठाया गया, क्योंकि ईरान, अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था।' रिपोर्ट के अनुसार, देश में मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले की गई इस कार्रवाई से लगता है कि ईरान के साथ स्थिति अभी भी सुलझी नहीं है और सैन्य टकराव की संभावना अभी भी बनी हुई है।

इस हमले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने जानबूझकर इस हमले को गुप्त रखा, ताकि बचाव के इस कदम को जरूरत से ज्यादा तूल न मिले। उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद अमेरिकी संपत्तियों की सुरक्षा करना था। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि तेहरान के साथ कूटनीति अभी भी काम कर रही है और एक समझौता 'हो सकता है। ट्रंप ने सोमवार रात फॉक्स न्यूज पर एक कार्यक्रम में ईरान में नए हमलों की खबरों पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं



कहा, लेकिन ईरान में युद्ध शुरू करने के अपने फैसले का बचाव किया और संकेत दिया कि हाल के दिनों में कोई लड़ाई नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा, 'यह हलका युद्ध है। यह भीषण युद्ध नहीं है। अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो युद्ध हो सकता है। लेकिन वे बहुत शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं और इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर लें।'

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी सोमवार को कुछ ऐसा ही रुख अपनाते हुए पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और ईरान ने युद्ध को खत्म करने की दिशा में 'कुछ प्रगति' की है। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'ईरानी हमेशा थोड़े अप्रत्याशित होते हैं और जैसा कि राष्ट्रपति हमेशा कहते हैं कि उनके पास सैन्य और गैर सैन्य दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन हमने निश्चित रूप से कुछ प्रगति की है। देखते हैं कि क्या हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कतर की अगुवाई में तीन दिनों तक चली अप्रत्यक्ष और बंद दरवाजे की बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ईरान ने सोमवार को कहा कि 'अब गेंद अमेरिका के पाले में है।' हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ बातचीत में प्रगति का संकेत दिया। इससे पहले ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि रविवार को उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अच्छी बातचीत। उनसे ईरान युद्ध पर चर्चा की गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत को आगे बढ़ने दिया जाए, जबकि नेतन्याहू ईरान पर हमले फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। चुनाव के दिन से पहले सोमवार को लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल पर अपने आखिरी भाषण के दौरान ट्रंप ने कई बार ईरान का जिक्र किया और कहा, 'यह कोई युद्ध नहीं है।' उल्लेखनीय है कि केशम द्वीप ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर से लगभग 14 मील दूर है। यह होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले यातायात पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध से पहले हर दिन लगभग 2 करोड़ (20 मिलियन) बैरल तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता था। इस युद्ध के दौरान अमेरिका पहले भी इस द्वीप को निशाना बना चुका है।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता लियू हैक्सिंग पाकिस्तान के दौरे पर, संबंधों को और मजबूत करने पर जोर

इस्लामाबाद,एजेंसी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू हैक्सिंग ने सोमवार को पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने बताया कि लियू हैक्सिंग एक नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लियू ने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान शहबाज ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए निरंतर राजनीतिक जुड़ाव और पार्टियों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लियू और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान और चीन के बीच एक बेहद मजबूत, समय की कसौटी पर खरी उतरी और हर मौसम में कायम रहने वाली रणनीतिक सहकारी साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती आपसी विश्वास, सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर टिकी है। शहबाज ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश,



कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि के आधुनिकीकरण में सहयोग बढ़ाने पर दोनों पक्षों के साझा फोकस को रेखांकित किया। लियू ने चीनी नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं दीं और पाकिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को और गहरा करने के लिए बीजिंग की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर करीबी समन्वय और सहयोग बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने दौरे पर आए चीन के नेता और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक भोज का भी आयोजन किया। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती स्थितियों और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। फील्ड मार्शल मुनीर ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लगातार उच्च-स्तरीय बातचीत, मजबूत संस्थागत संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। चीनी प्रतिनिधि ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में पाकिस्तान के योगदान की सराहना की और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर भरोसा जताया। एक अन्य बैठक में, उप प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री इशाक डार ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही, उन्होंने करीबी समन्वय बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

ढाका का मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र हुआ अशांत, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

ढाका (बांग्लादेश),एजेंसी। देश की राजधानी ढाका का मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र अशांति की चपेट में आ गया है। यहां के कपड़ा उद्योग के कर्मचारी तीन दिन से न्यूनतम वेतनमान 30 हजार टका करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आसपास के लोग डर के साये में हैं। आज कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा। बावजूद इसके तनाव व्याप्त है।

ढाका ट्रिब्यून और बांग्ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों और पुलिस के बीच बार-बार हुई भागदौड़ और टकराव ने इलाके के कुछ हिस्सों को मानो युद्ध के मैदान में बदल दिया है। मीरपुर-10, मीरपुर-2, मीरपुर-14 और मीरपुर-11 में दहशत फैल गई है। जरूरी काम न होने पर लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मीरपुर के पुराबी इलाके में रहने वाले अबू हनीफ ने बताया, 'रविवार से ही यह इलाका किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। सुबह ठीक से जागने से पहले ही साउंड ग्रेनेड की तेज आवाजें और आंसू गैस की तीखी गंध ने जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने बताया कि आज सुबह से लेकर दोपहर तक इलाके में तनाव बना रहा। कर्मचारी और पुलिस सड़कों पर एक-दूसरे का पीछा करते रहे। अबू ने कहा, 'कई लोग बाहर जाने से डर रहे हैं। हमें तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की भी चिंता हो रही है।' शरीफुल इस्लाम ने बताया कि आम लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है और लोगों से पूछताछ करने के लिए गलियों में घुस रही है। इससे पूरे इलाके में दहशत है।'

मीरपुर-2 के निवासी कौसर ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बीच इलाके में कोई भी शांति से नहीं रह पा रहा है। उन्होंने कहा, 'चूंकि लगातार झड़पें हो रही हैं, इसलिए हर कोई डर के साये में है।' गृहिणी शरीफा बेगम ने कहा, 'हमें डरते-डरते बाहर निकलना पड़ता है। कल मैं एक बार बाहर गई थी, लेकिन मुझे तुरंत वापस घर लौटना पड़ा। उसके बाद से मैं बाहर नहीं जा पायी हूं। हर तरफ डर का माहौल है। इलाके में आज चाय की दुकानें बंद मिलीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। सड़क किनारे मौजूद कई बड़ी दुकानें भी बंद मिलीं। कपड़ा उद्योग के कर्मचारी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और 30,000 टका के न्यूनतम मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों के पुलिस की गाड़ी में आग लगा देने से आंदोलन हिंसक हो गया है। मीरपुर में मंगलवार सुबह कई जगहों पर पुलिस और कर्मचारियों के बीच फिर तीखी झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड छोड़े। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने भी पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि उपद्रव फैलाने के आरोप में सोमवार को लगभग छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले दो दिनों में हुई झड़पों को लेकर 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 10 हजार से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है।

एक नजर

पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान शुरू, घर बैठे जमा कर सकते हैं प्रमाण पत्र

नई दिल्ली,सद्भावना टुडे। कोषागार उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली-भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान नवंबर 2026 के तहत अब पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी श्रीमती ज्योति विपिन भदौरिया ने बताया कि पेंशनर अपने मोबाइल में Aadhar Face RD और Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करके घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स की सुविधा के लिए कोषागार कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। इसके अलावा बैंकों और पोस्ट ऑफिसों द्वारा भी ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र की सुविधा दी जा रही है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए कोषागार कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली के टेलीफोन नंबर 011-26110847 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली ने सभी पेंशनर्स से ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से ही प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की है।

एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक का शेयर पहले दिन 29 फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद

नई दिल्ली,एजेंसी। पर्यावरण प्रौद्योगिकी कंपनी एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद अपने 330 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 29 फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। अपशिष्ट जल शोधन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर शेयर निर्गम मूल्य से 7.28 फीसदी की बढ़त के साथ 354.05 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कारोबार के अंत में ये 28.74 फीसदी उछलकर 424.85 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयर 7.60 फीसदी की बढ़त के साथ 355.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कारोबार के अंत में यह 29.12 फीसदी चढ़कर 426.10 रुपये पर बंद हुआ है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,161.69 करोड़ रुपये रहा। एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को पिछले हफ्ते गुरुवार को बोली के अंतिम दिन 9.47 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 668 करोड़ रुपये के अपने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 313 से 330 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी की योजना नए शेयर जारी कर जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की है। एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। ये एक पर्यावरण प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो अपशिष्ट जल उपचार (डब्ल्यूडब्ल्यूटी), अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग (डब्ल्यूआरआर), तथा ठोस अपशिष्ट उपचार (एसडब्ल्यूटी) के क्षेत्रों में कुशल तकनीकें और व्यापक इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है।

स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 14 फीसदी बढ़कर 23,038 करोड़ रुपये पर

नई दिल्ली। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे की घोषणा कर दी है। जुलाई-सितंबर में बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 14 फीसदी बढ़कर 23,038 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 20,160 करोड़ रुपये रहा था। एसबीआई ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैंक की कुल आय चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 1,43 ,796 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,34,979 करोड़ रुपये रही थी। बैंक की ब्याज आय आलोच्य तिमाही में बढ़कर 1,32,019 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,19,654 करोड़ रुपये रही थी। बैंक के मुताबिक एसबीआई की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल कर्ज के प्रतिशत के रूप में सितंबर को समाप्त तिमाही में घटकर 1.39 फीसदी रहीं। पिछले साल यह आंकड़ा 1.73 फीसदी रहा था।

पंजाब सरकार के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस

चंडीगढ़,एजेंसी। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को 17 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अदालत ने सरकार से पूछा है कि महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर दिए गए आदेशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी। मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपील से जुड़ी सभी तकनीकी कमियों को दूर कर लिया गया है और अगले सप्ताह मामले की सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि अदालत के पूर्व आदेशों को लागू क्यों नहीं किया गया। अदालत ने इसे अवमानना से जुड़ा मामला मानते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले भी इसी मामले में हाई कोर्ट के मुख्य सचिव पर जुर्माना लगा चुका है। इसके बावजूद आदेशों के पालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर अदालत ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य



सचिव की ओर से अदालत में पेश की गई जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की विभिन्न देनदारियों के रूप में कुल 32,418 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें से लगभग 22,818 करोड़ से 22,828 करोड़ रुपये की राशि केवल महंगाई भत्ते के बकाये से संबंधित बताई गई है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ते का यह बकाया 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर तक की अवधि से संबंधित है। महंगाई भत्ते के भुगतान का मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में हाई कोर्ट के ताजा आदेश ने पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर यह बताना होगा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

कमल का भी एक मौसम होता है, वह साल भर नहीं खिलता-उपमुख्यमंत्री

जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को भाजपा नेता राम माधव की केंद्र शासित प्रदेश यात्रा को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमल का भी एक मौसम होता है, वह साल भर नहीं खिलता। भाजपा नेता की यह यात्रा केंद्र शासित प्रदेश में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच हुई है जिसमें श्रीनगर के लोकसभा सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी नेतृत्व पर अनुच्छेद 370 की बहाली सहित प्रमुख चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव जम्मू और कश्मीर में पार्टी मामलों और चुनावी भूमिकाओं को संभालने वाले एक प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने 2015 की भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार और उसके साझा न्यूनतम कार्यक्रम को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। जम्मू और कश्मीर में कथित राजनीतिक घटनाक्रम और माधव की यात्रा के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि हर चीज का एक समय होता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चर्चाओं के लिए यह उचित समय है। भाजपा के चुनाव चिन्ह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हर फूल का अपना मौसम होता है। उन्होंने जम्मू में पत्रकारों के सामने कहा कि सर्दी आ रही है। कमल खिलेगा, मुरझाएगा और चला जाएगा। रुहुल्लाह का इस्तीफा राष्ट्रीय कांग्रेस का आंतरिक मामला है चौधरी ने कहा कि उन्हें माधव के विशिष्ट कार्यक्रम की जानकारी नहीं है और न ही उन्हें यह पता है कि वे राजनीतिक नेताओं से चर्चा करने या मीडियाकर्मियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वे चर्चा करने, मीडिया से मिलने या आप लोगों से मिलने आ रहे हों। मुझे नहीं पता। हमारे पास ऐसे किसी कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में कथित राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। 2024 में एनसी टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए रुहुल्लाह ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए 80 मिनट के भाषण में जम्मू-कश्मीर में एक नया राजनीतिक दल बनाने का संकेत दिया। यह घटनाक्रम हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एनसी विधायकों के बीच कथित असंतोष के बाद सामने आया है।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 510 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। माना जा रहा है कि सोने के भाव में धनतेरस और दिवाली की वजह से तेजी का ये माहौल बना है। दूसरी ओर चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुरुआती कारोबार में आज भी ये चमकीली धातु सोमवार के भाव पर ही बिक रही है। भाव में बदलाव आने के कारण देश के अलग-अलग सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम के पुराने स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,39,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,810 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश : ए.के. शर्मा



सैफुल्लाह सिद्दिकी, रिपोर्टिंग

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और निवेश के नए अवसरों के माध्यम से प्रदेश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 के दौरान कही।

समिट में मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की कार्ययोजना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में सौर ऊर्जा, बायोएनर्जी और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम, सोलर सिटी और यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को आम नागरिकों, किसानों और उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का महत्वपूर्ण आधार भी है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ-साथ कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और बायोएनर्जी परियोजनाओं में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

यूपीनेडा ने प्रदर्शित कीं प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं

समिट में उत्तर प्रदेश की नोडल एजेंसी यूपीनेडा की ओर से प्रदेश की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इनमें सोलर सिटी, यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाएं, कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), बायोएनर्जी परियोजनाएं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) प्रमुख रूप से शामिल रहीं। मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, उद्योग जगत की भागीदारी और निवेशकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।

देश-विदेश के निवेशक और विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा

2 से 5 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित इस समिट में देश-विदेश के नीति निर्माता, निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और विभिन्न राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नोडल एजेंसियां भाग ले रही हैं। इस आयोजन से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, निदेशक रविन्द्र सिंह, सचिव पंकज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उल्लास-उमंग के पर्वों में न हो कोई अप्रिय घटना, सौहार्द और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ,एजेंसी। आगामी पर्व-त्योहार उल्लास, उमंग, आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इन अवसरों पर प्रदेश में सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना पर्वों के उल्लास में खलल न डाल सके। मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए। दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के दृष्टिगत शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हुए अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने अथवा शरारतपूर्ण बयानबाजी से माहौल बिगाड़ने वालों पर त्वरित व प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में सात नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि अंतरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हो तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर जनसामान्य के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।

प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर चौबीसों घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। धनतेरस और दीपावली के दृष्टिगत मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24म7 पुलिस निगरानी, सघन पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और पीआरवी-112 निरंतर सक्रिय रहे। प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रमों में नियमानुसार समयबद्ध अनुमति दी जाए। ऐसे आयोजनों की आड़ में दुर्भावनापूर्ण ढंग से विवाद खड़ा करने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएं। पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले व सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेंडरों और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग को मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग कराई जाए तथा कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर अथवा सड़कों पर गड्ढों की स्थिति न रहे। पर्वों के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोस्टरमुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा शुद्ध पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश देते हुए कहा गया कि अनफिट और डग्गामार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। घटतौली की शिकायत मिलने पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए, जो दूसरों के लिए नजीर बने। सेवानिवृत्त पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए।

धनतेरस-दीपावली पर बाजारों में बढ़ेगी पुलिस की चौकसी, सर्राफा बाजारों पर विशेष नजर

झांसी,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में आगामी धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को झांसी पहुंचीं अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने रिजर्व पुलिस लाइन में झांसी रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने बाजारों, विशेषकर सर्राफा बाजारों और भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन पहुंचने पर एडीजी को गार्द द्वारा सलामी देकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभागार में आयोजित समीक्षा गोष्ठी में पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र आकाश कुलहरि सहित रेंज के विभिन्न जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्षेत्राधिकारी और झांसी जनपद के थाना प्रभारी मौजूद रहे।



समीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, लंबित मुकदमों, विवेचनाओं के निस्तारण, वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध और जनशिकायतों के निस्तारण की बिंदुवार समीक्षा की गई। एडीजी ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने तथा साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। थानों पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध निस्तारण करने और पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। त्योहारों की सुरक्षा को लेकर एडीजी ने बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, नियमित पैदल गश्त करने और संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा अतिक्रमण हटवाकर आवागमन सुगम बनाने को भी कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)